घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 172- शुक्रवार 24 - अप्रैल 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

बंगाल में वोटिंग का नया रिकॉर्ड...पहले फेज में 92 प्रतिशत मतदान

ममता बोलीं...एसआईआर के विरोध में बंपर वोटिंग,तमिलनाडु के इतिहास में सबसे ज्यादा 85 प्रतिशत वोट पड़े

कोलकाता/चेन्नई,23 अप्रैल 2026। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में गुरुवार को बंपर वोटिंग हुई। बंगाल की 294 सीटों में से 152 सीटों पर पहले फेज में 92.10% मतदान हुआ। वहीं,तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 84.95% वोटिंग हुई। दोनों राज्यों में आजादी के बाद अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। इससे पहले तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मतदान 2011 में 78.29% था,जबकि बंगाल में 2011 में 84.72% मतदान दर्ज किया गया था। ममता ने वोटिंग के बाद कहा...बंगाल की जनता ने एसआईआर के खिलाफ बंपर वोटिंग की है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि टीएमसी का सूरज ढल चुका है। इससे पहले असम, केरलम और पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल को रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी। असम के इतिहास में सबसे ज्यादा 85.91%,पुडुचेरी में 90% और केरलम में 1987 के बाद सबसे ज्यादा 78.27% वोटिंग हुई थी। पाचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को एकसाथ आएंगे। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग,जलपाईगुड़ी,अलीपुरद्वार,कूचबिहार, उत्तर दिनाजपुर,दक्षिण दिनाजपुर,मालदा, मुर्शिदाबाद,बीरभूम,पश्चिम बर्धमान,पुरुलिया, बांकुड़ा,झाड़ग्राम,पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर जैसे जिलों में मतदान हुआ। ये सभी जिले भौगोलिक और सामाजिक रूप से विविधता वाले क्षेत्र हैं,जिनमें सीमावर्ती इलाके, चाय बागान क्षेत्र,आदिवासी बहुल क्षेत्र,ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी केंद्र भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के अनुसार प्रथम चरण में लगभग 3.6 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र थे। कुल 44,376 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 5644 मतदान केंद्रों का संचालन महिलाकर्मियों द्वारा किया गया, जबकि 207 मतदान केंद्रों को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया गया था।

सुरक्षा की दृष्टि से यह चरण अबतक के सबसे सख्त इंतजामों में से एक माना जा रहा है। पूरे राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 2407 कंपनियां तैनात की गईं। संवेदनशील और अति-संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त निगरानी, ड्रोन सर्विलांस, फ्लाइंग स्क्वॉड और विशेष पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई। मतदान के दौरान अधिकांश सीटों पर भारी उत्साह देखने को मिला और कई जिलों में मतदान 90 प्रतिशत से अधिक दर्ज किया गया। दक्षिण दिनाजपुर सबसे आगे रहा, जहां 93.12 प्रतिशत मतदान हुआ। केवल कालिम्पोंग ऐसा जिला रहा जहां मतदान 81.98 प्रतिशत रहा। हालांकि, पहले चरण के मतदान के दौरान कुछ हिस्सों में छिटपुट हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज में भाजपा प्रत्याशी पर हमले का आरोप लगा, जबकि बीरभूम के लाभपुर में भाजपा एजेंट के घायल होने की घटना सामने आई। इसी जिले के खैराशोल में ईवीएम खराबी के बाद मतदान रुका, जिसके बाद पथराव और पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की खबरें आईं, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी का सिर फट गया।

बंगाल में वोटिंग के दौरान मारपीट-झड़प की घटनाएं...

- बंगाल के दक्षिण मिदनापुर में कुमारगंज सीट से भाजपा कैंडिडेट सुवेंदु सरकार को भीड़ ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। उनका सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ था। इसके बावजूद भीड़ ने उन्हें खदेड़ दिया।
- पश्चिम बर्धमान जिले के बर्नपुर में आसनसोल साउथ सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर हमला हुआ। इससे गाड़ी के पीछे का शीशा टूट गया। अग्निमित्रा ने बताया कि उनकी कार पर पत्थर फेंके गए।
- बीरभूम के बोधपुर गांव में EVM खराब होने के बाद लोगों ने पुलिस और सेंट्रल फोर्स पर पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। घटना में कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए।
- मुर्शिदाबाद के नौदा में देसी बम से हमले में कई लोग घायल हो गए। आम जनता उन्नयन पार्टी चीफ हुमायूं कबीर सुबह घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थकों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, पथराव हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हुमायूं की कार पर पत्थरों और लाठियों से हमला किया गया।
- सिलीगुड़ी के जगदीश चंद्र विद्यापीठ में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बूथ के बाहर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो गई। विवाद बढ़ता देख सुरक्षाबलों ने दोनों पक्षों को शांत कराया। यहां से शंकर घोष भाजपा प्रत्याशी हैं।

बहरामपुर में दिख रहा एसाईआर का असर : कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और क्षेत्र के माहौल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सत्ता विरोधी लहर (एंटी-इंकबेंसी) के साथ-साथ एसाईआर (स्पेशल ऑब्जर्वर रिपोर्ट/सिस्टम) का स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चौधरी ने कहा कि हालांकि कांग्रेस ने शुरुआत से ही इस व्यवस्था का विरोध किया था, लेकिन इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव आयोग की सख्ती के कारण क्षेत्र में गुंडागर्दी में काफी कमी आई है।

दोनों राज्यों के हर मतदाता को सलाम : ज्ञानेश कुमार

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग दोनों राज्यों के हर मतदाता को सलाम करता है।'

वोट प्रतिशत हमारी जीत का संकेत : कुणाल घोष

टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा,'वोटों के इस प्रतिशत की उम्मीद थी। कुछ असली वोटरों के नाम हटा दिए गए और उन्हें बाहर कर दिया गया। यह चुनाव ममता बनर्जी के पक्ष में है और भाजपा की 'बंगाल-विरोधी' नीतियों के खिलाफ है। 152 सीटों में से हम कम से कम 125 सीटें जीतने जा रहे हैं, यह आंकड़ा 133 से 135 तक भी जा सकता है। इसलिए यह जीत का एक स्पष्ट संकेत है।'

149 दिन बाद खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट,श्रद्धालुओं में खास उत्साह

चमोली,23 अप्रैल 2026। उत्तराखंड की विश्वप्रसिद्ध चारधाम यात्रा के तहत चमोली जिले स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट गुरुवार सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर विधिवत रूप से खोल दिए गए। करीब 149 दिनों बाद मंदिर के द्वार खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कपाट खुलने के बाद सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान बद्रीविशाल के दर्शन किए। उनके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसर में कपाट खुलने के समय लगभग 2 हजार श्रद्धालु मौजूद थे। परंपरा के अनुसार, सबसे पहले पिछले छह महीनों से जल रही अखंड ज्योति के दर्शन कराए जा रहे हैं। कपाट बंद होने के दौरान भगवान बद्रीविशाल की प्रतिमा को ढकने के लिए चढ़ाया गया घृत कंबल भी हटाया गया। बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल के अनुसार इस वर्ष कंबल घी से पूरी तरह लबालब मिला, जिसे आने वाले समय में अनुकूल मौसम और समृद्धि का संकेत माना जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, यह घृत कंबल माणा गांव की कुंवारी कन्याओं द्वारा उपवास रखकर एक ही दिन में तैयार किया जाता है। ऊन से बने इस कंबल को शुद्ध घी में डुबोकर भगवान को अर्पित किया जाता है। छह माह तक बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के बावजूद कंबल की स्थिति को भविष्य के संकेत के रूप में देखा जाता है।

आरबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को दी बड़ी राहत

ऑटो डेबिट पेमेंट के नियमों में किया बड़ा बदलाव

नई दिल्ली,23 अप्रैल 2026। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए ऑटो डेबिट के नियमों में अहम बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक ने डिजिटल पेमेंट के लिए नया ई-मैंडेट फ्रेमवर्क जारी कर दिया है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य यूजर्स के डिजिटल लेनदेन को सरल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। इस बदलाव के बाद अब ग्राहकों को बार-बार होने वाले ऑनलाइन पेमेंट्स पर पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल मिलेगा और बिना उनकी मर्जी के खाते से पैसे कटना मुश्किल हो जाएगा। आरबीआई के नए ई-मैंडेट फ्रेमवर्क के मुताबिक, अब बार-बार होने वाले पेमेंट्स यानी ऑटो डेबिट के लिए 15,000 रुपये की नई लिमिट तय कर दी गई है। सबसे बड़ी राहत यह है कि इस लिमिट तक के ऑटो-पेमेंट के लिए अब ग्राहकों को ओटीपी या पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, सुरक्षा के लिहाज से ग्राहकों को पहली बार रजिस्ट्रेशन करते समय एक बार एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एएफए) पूरा करना होगा। इसके बाद तय लिमिट के भीतर का पेमेंट अपने आप हो जाएगा, लेकिन 15,000 रुपये से ज्यादा के किसी भी लेनदेन के लिए ओटीपी के जरिए अतिरिक्त सत्यापन करना अनिवार्य होगा।

फ्रांस के हवाई अड्डों पर भारतीयों को ट्रांसिट वीजा से मिली छूट

नई दिल्ली,23 अप्रैल 2026। फ्रांस ने अपने यूरोपीय क्षेत्र के हवाई अड्डों से पारगमन सुविधा का इस्तेमाल करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांसिट वीजा लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। गत 10 अप्रैल से लागू इस निर्णय के तहत भारतीय यात्री आगे के गंतव्य के लिए विमान बदलने के लिए यदि किसी फ्रांसीसी हवाई अड्डे का इस्तेमाल करते हैं तो अब उन्हें इसके लिए ट्रांजिट वीजा नहीं लेना होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में गुरुवार को नियमित प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी देते हुए कहा कि फ्रांस से होकर केवल हवाई मार्ग से पारगमन करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए अब 10 अप्रैल 2026 से ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता खत्म हो गई है। उन्होंने बताया कि यह कदम भारत और फ्रांस के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझीदारी को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान इस विषय पर सहमति बनी थी। इसके बाद इसे लागू किया गया है।

झालमुड़ी मैंने खाई,झाल उन्हें लग रही : पीएम मोदी

कहा...4 मई को परिणाम नहीं,परिवर्तन होगा,टीएमसी की हार ही भय की हार है...

कोलकाता,23 अप्रैल 2026। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बंगाल के मथुरापुर और कृष्णानगर में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा...यहां पूरे बंगाल से उत्साही नागरिक आए हैं। जनता ने तय कर दिया है कि 4 मई को परिणाम नहीं, परिवर्तन आएगा। टीएमसी हारेगी और भाजपा का भरोसा जीतेगा। महिला आरक्षण पर बोलते हुए मोदी ने कहा कि बंगाल की धरती मां दुर्गा को पूजती है, लेकिन टीएमसी ने महिला आरक्षण के खिलाफ वोटिंग की। यह महिलाओं का अपमान है। टीएमसी की सरकार में गुंडों और बलात्कारियों को खुला संरक्षण मिला हुआ है। बंगाल की बेटियां ये अत्याचार कभी नहीं भूल सकतीं। चुनाव प्रचार के दौरान झालमुड़ी खाने पर उन्होंने कहा- झालमुड़ी मैंने खाई है और झाल उन्हें लग रही है। मैं चुनाव आयोग का अभिवादन करता हूं कि वह बंगाल में शांतिपूर्वक चुनाव करवा पा रहे हैं। अब का मतदान सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मैं यहां परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। अब तक का मतदान सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मैं यहां परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। मैं सभी मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि इस बार वोटिंग के नए रिकॉर्ड बनने चाहिए। 4 मई के बाद बंगाल में सुरक्षा की गारंटी आने वाली है।

पीएम ने कहा...टीएमसी को अपने हितों की चिंता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल की निर्मम सरकार को सिर्फ अपने हितों की चिंता है, उसे आपके सुख-दुख से कोई लेना-देना नहीं है। इसका एक उदाहरण है, मथुरापुर का भंग मेला... भंग मेले को राज्य सरकार से वह समर्थन नहीं मिला जो मिलना चाहिए था।

मोदी बोले...सभी दल महिला विरोधी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी और इन सारे दलों का महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। कुछ दिन पहले संसद में जो कुछ हुआ आपने देखा है। भाजपा सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रस्ताव लेकर संसद में आई थी लेकिन टीएमसी ने इसके खिलाफ वोटिंग की। उन्होंने बंगाल की माताओं का अधिकार छीना। टीएमसी ने यहां महिलाओं के सम्मान को जो ठेस पहुंचाई है उसका हिसाब आपका वोट करेगा।

पीएम मोदी बोले...परिवर्तन की कमान बहनों ने संभाल रखी है...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मैं साफ देख रहा हूं बंगाल में इस बार परिवर्तन की कमान बंगाल की बहनों ने संभाल रखी है क्योंकि निर्मम सरकार की सबसे बड़ी शिकार महिलाएं रही हैं। आए दिन बलात्कार,आरजी कर और संदेशखाली जैसी घटनाएं बलात्कारियों और गुंडों को टीएमसी का खुला सरंक्षण है।

पीएम मोदी ने कहा...टीएमसी चुनाव के बाद गायब हो जाती है...

पीएम मोदी ने बंगाल के मथुरापुर में जनसभा में कहा कि टीएमसी ने 2000 बड़ी इंडस्ट्री लगाने की बात कही थी, वह भी एक धोखा था। यहां मथुरापुर में भी लोगों से बड़े वादे किए गए थे, लेकिन यहां कुछ नहीं हुआ। टीएमसी चुनाव से पहले वादे करती है, लेकिन चुनाव के बाद गायब हो जाती है। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में मोदी ने कहा कि यहां मथुरापुर के अलावा डायमंड हार्बर, जयनगर और दूसरी जगहों से भी उत्साही नागरिक आए हैं। आपने यहां आकर अपना फैसला भी सुना दिया है। आपने यह तय कर दिया है कि 4 मई को केवल परिणाम नहीं परिवर्तन आएगा।

टिहरी में भीषण हादसा...खाई में गिरी कार,8 लोगों की मौत से मचा कोहराम

टिहरी,23 अप्रैल 2026। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में गुरुवार को एक सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई,जबकि दो अन्य घायल हो गए। हादसा चंबा-कोटि मार्ग पर नैल के पास उस समय हुआ जब एक यूटिलिटी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। दुर्घटना की सूचना डायल 112 के माध्यम से मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ,फायर सर्विस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं। एसडीआरएफ की ओर से स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। अब तक दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए भेजा गया है। हादसे में घायल दो व्यक्तियों को जिला अस्पताल बौराड़ी में भर्ती कराया गया है। दोनों घायलों की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। सड़क हादसे में मृतक और घायल सभी लोग घनसाली क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, सभी लोग ऋषिकेश से एक क्रियाकर्म में शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी नैल के पास उनका वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। जानकारी के अनुसार वाहन में 10 लोग सवार बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है,हालांकि स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।घायलों में उत्तम (30) पुत्र पुस्सू, निवासी ग्राम लोस्तु बड़ियारगढ़ तथा अंकित (22) पुत्र आशा लाल, निवासी ग्राम नेलचामी, घनसाली शामिल हैं। घटनास्थल पर जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल,टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, शक्तिलाल शाह और नगरपालिका अध्यक्ष आनंद बिष्ट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे मौजूद रहकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन ने घायलों को शीघ्र उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

वर्षों के अनुशासित प्रयासों और त्याग की परिणति है दीक्षांत समारोह : उपराष्ट्रपति

ऋषिकेश,23 अप्रैल 2026। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि दीक्षांत समारोह न केवल वर्षों के अनुशासित प्रयासों और त्याग की परिणति है, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत भी है। उन्होंने स्नातकों से समर्पण और उद्देश्य की भावना के साथ अपने पेशेवर कर्तव्यों को निभाने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन गुरुवार को ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने छात्र छात्राओं को पदक और उपाधियां वितरित कीं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दीक्षांत समारोह न केवल वर्षों के अनुशासित प्रयासों और त्याग की परिणति है,बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत भी है। उन्होंने स्नातकों से समर्पण और उद्देश्य की भावना के साथ अपने पेशेवर कर्तव्यों को निभाने का आग्रह किया। उन्होंने ऋषिकेश को चिंतन और उपचार का वैश्विक केंद्र और हिमालय का प्रवेश द्वार बताते हुए उसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसा वातावरण दीक्षांत समारोह की गंभीरता को और भी गहरा कर देता है।

पांच साल बाद चीन के पर्यटकों को वीजा जारी करेगा भारत

नई दिल्ली,23 अप्रैल 2026। भारत सरकार चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है। करीब पांच साल पहले गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद इन सेवाओं को बंद कर दिया गया था। अब दोनों देशों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ धीरे-धीरे पिघल रही है। यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों में धीरे-धीरे आ रही नरमी के बीच उठाया गया है। हाल ही में भारत और चीन ने सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही लंबे समय से रुकी हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी दोबारा बहाल कर दिया गया है। नए वीजा नियम मुख्य चीन,हांगकांग और मकाऊ से आने वाले यात्रियों पर लागू होंगे। सरकार का यह फैसला पर्यटन,व्यापार और लोगों के बीच आपसी मेलजोल को फिर से बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है।

बंगाल के पुरसुराह विधानसभा में अमित शाह ने भरी हुंकार.....

'हर घुसपैठिए को चुन-चुनकर बाहर निकालेंगे'

कोलकाता,23 अप्रैल 2026। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक पारा बहुत गर्म हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के पुरसुराह में एक बहुत बड़ी जनसभा की है। इस रैली में उन्होंने राज्य की मौजूदा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। अमित शाह ने जनता से साफ कहा है कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है, तो एक-एक घुसपैठिए को बंगाल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अमित शाह ने अपनी इस जनसभा में घुसपैठ,किसानों की परेशानी और राज्य की कानून-व्यवस्था जैसे बड़े मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आज बंगाल के हर कोने में टीएमसी सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। जनता अब इस सरकार से पूरी तरह परेशान हो चुकी है और बदलाव चाहती है। उनका दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ यह गुस्सा आने वाले चुनाव के नतीजों में साफ दिखाई देगा और जनता सिर्फ कमल खिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

घुसपैठियों को लेकर अमित शाह ने क्या बड़ा दावा किया? केंद्रीय गृह मंत्री ने घुसपैठ को बंगाल की सबसे बड़ी समस्या बताया है। उन्होंने कहा कि यहां से घुसपैठियों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। शाह ने आरोप लगाया कि जब मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम हटाए जाते हैं,तो दीदी (ममता बनर्जी) को बहुत तकलीफ होती है। उन्होंने जनता से अपील की कि 5 तारीख को भाजपा की सरकार बना दें।

संपादकीय

होर्मुज आपदा में भारत के लिए अवसर

अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम का विस्तार इस ओर संकेत करता हैं कि होर्मुज जलमार्ग का खुलना संभव है। वैसे यदि ऐसा हो जाता है तो भी पूर्ववर्ती व्यवस्था की वापसी संभव नहीं लगती। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले खाड़ी क्षेत्र की सामुद्रिक परिवहन व्यवस्था एक नाजुक धारणा पर टिकी थी।

करीब 130 जहाज रोजाना इस 33 किमी चौड़े संकरे जल मार्ग से बिना किसी बाधा के गुजरते थे,पर अब यह धारणा ध्वस्त हो चुकी है। आर्थिक दृष्टि से इसका अर्थ है कि होर्मुज के पुनः खुलने के बाद भी बीमा लागत ऊंची रह सकती है। शिपिंग कंपनियां इस मार्ग पर निर्भरता घटाने के लिए अपने मार्गों का पुनर्निर्धारण करने में लगी हैं।

खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी देश भी समानांतर रूप से खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा के अपने ढांचे की समीक्षा कर रहे हैं। यह केवल भू-राजनीतिक व्यवधान नहीं है। यह वैश्विक व्यापार संरचना का पुनर्संयोजन भी है। इसमें उन मार्गों, वित्तीय तंत्रों और संस्थागत व्यवस्थाओं का पुनर्गठन हो रहा है, जो तय करते हैं कि सीमा पार वस्तुओं का व्यापार कैसे संचालित होता है।

इस उभरते परिदृश्य में भारत विशिष्ट रूप से सशक्त स्थिति में है। दशकों से भारत को मुख्यतः एक ऊर्जा-निर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में देखा गया है, जो एक बड़ी हद तक खाड़ी क्षेत्र के तेल एवं गैस पर निर्भर है।

होर्मुज संकट ने इस सच को भी उजागर किया है कि भारत केवल खरीदार नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता भी है, विशेष रूप से खाद्य और आवश्यक वस्तुओं के मोर्चे पर। यह शक्ति संतुलन को सूक्ष्म, पर महत्वपूर्ण रूप से बदलने वाला पहलू है।

भारत की शक्ति इस बिंदु में निहित है कि वह एक साथ कई संबंधों को संभालने में सक्षम है। उसके ईरान के साथ रणनीतिक संबंध हैं तो संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ भी वह अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रहा है। सऊदी अरब, कुवैत और कतर के साथ उसके ऊर्जा संबंध इस क्षेत्र में उसकी केंद्रीय भूमिका को और सुदृढ़ करते हैं। केवल यूएई में ही 43 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी समुदाय आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों की कड़ियों को कुछ ऐसे जोड़ता है, जिसका कोई तोड़ नहीं।

भारत और यूएई के बीच स्थानीय मुद्राओं के माध्यम से व्यापार अब अमेरिकी डालर के बजाय रुपये और दिरहम में संभव है। इससे मुद्रा उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक वित्तीय जोखिमों का प्रभाव कम होता है। ऐसी सुविधा मौजूद संकट के समय और महत्वपूर्ण हो जाती है।

होर्मुज संकट ने खाड़ी क्षेत्र की खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमजोरियों को स्पष्ट कर दिया है। दशकों तक लचीलापन उनकी प्राथमिकताओं में नहीं था, जबकि आज प्राथमिकता निर्णायक रूप से बदल गई है। खाड़ी की अर्थव्यवस्थाएं अब केवल सस्ते आपूर्तिकर्ता की तलाश में नहीं हैं, बल्कि सबसे भरोसेमंद साझेदार को प्राथमिकता दे रही हैं।

यही वह बिंदु है,जहां भारत की भूमिका निर्णायक बन जाती है। यह संकट एक नई आपूर्ति श्रृंखला के विकास की परिस्थितियों को भी निर्मित कर रहा है। इस संभावित श्रृंखला के अंतर्गत जहां भारत एक उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित होगा, वहीं खाड़ी क्षेत्र लाजिस्टिक्स हब और वितरण केंद्र के रूप में उभरेगा। इससे समूची आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्संयोजन होगा, जिसमें लचीलेपन के साथ ही वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी एकीकृत होंगी।

अनियंत्रित गेमिंग के दौर के बाद नियंत्रण का कड़ा अध्याय

डिजिटल लत के भंवर से उबरने की नीतिगत पहल का आरंभ...
मनोरंजन से अनुशासन तक : गेमिंग जगत में बड़े बदलाव की शुरुआत...

प्रो.आर.के.जैन अरिजीत
बड़वानी,मध्यप्रदेश

रात की खामोशी अब विश्राम नहीं,बल्कि स्क्रीन की चमक में डूबकर एक नई सोच को जन्म दे रही है,जो अनजाने में पूरी पीढ़ी का मन गढ़ रही है। उंगलियों की निरंतर हलचल ने सोच की गहराई को कमज़ोर कर दिया है,और आभासी उपलब्धियों का आकर्षण वास्तविक जीवन की प्राथमिकताओं को पीछे धकेल रहा है। ऐसे नाज़ुक मोड़ पर 1 मई 2026 से लागू होने जा रहा ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ओजीएआई) केवल प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि डिजिटल अनुशासन को फिर से स्थापित करने का प्रभावी प्रयास है। यह पहल उस अनियंत्रित डिजिटल बहाव को थामने की शुरुआत है, जिसने युवाओं को लत, असंतुलन और मानसिक दबाव के जाल में फँसा दिया है।

डिजिटल जगत को संतुलित दिशा देने के उद्देश्य से प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट,2025 (प्रोगा) के तहत गठित ओजीएआई भारत के शासन में एक अहम बदलाव का संकेत है। यह स्वायत्त संस्था ऑनलाइन गेमिंग को तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत करेगी और रियल मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगी। सुरक्षित सोशल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन को अधिकांश मामलों में स्वैच्छिक रखा गया है। ओजीएआई को सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं,जिसमें गेम्स की राष्ट्रीय रजिस्ट्री तैयार करना,अनुपालन की निगरानी और अवैध गेम्स को ब्लैकलिस्ट करना शामिल है। वहीं,सुरक्षित और शैक्षिक खेलों को राष्ट्रीय रजिस्ट्री में शामिल कर उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा,ताकि गेमिंग केवल लत नहीं,बल्कि सीख और विकास का साधन बन सके।

स्क्रीन की चकाचौंध अब युवाओं को इस तरह बाँध रही है कि वास्तविक जीवन का संतुलन बिगड़ने लगा है। आज की युवा पीढ़ी जिस तरह ऑनलाइन गेमिंग के प्रभाव में फँसती जा रही है, वह महज़ सामाजिक चुनौती नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में चेतावनी दी गई है कि 15 से 29 वर्ष के युवाओं में अत्यधिक स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन गेमिंग से चिंता,अवसाद,अनिद्रा और ध्यान की कमी तेजी से बढ़ रही है। रियल मनी गेम्स से होने वाला आर्थिक नुकसान परिवारों की स्थिरता को भी डगमगा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण यह भी सुझाव देता है कि डिजिटल एडिक्शन से निपटने के लिए टेली-मानस जैसे मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को और मजबूत किया जाए। ओजीएआई का हस्तक्षेप इस बिगड़ती परिस्थिति को संभालने की दिशा में एक ठोस और समयानुकूल पहल है।

नियमन की कसौटी पर खरा उतरने वाला ढांचा तभी सार्थक होता है, जब उसमें अधिकार के साथ जवाबदेही भी स्पष्ट हो–और ओजीएआई इसी संतुलन

का सशक्त उदाहरण बनकर उभरता है। इसे सिविल कोर्ट के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं,जिससे यह गेम्स के वर्गीकरण,पंजीकरण और अनुपालन की निगरानी प्रभावी ढंग से कर सके। केंद्रीय शिकायत निवारण तंत्र उपयोगकर्ताओं को त्वरित न्याय उपलब्ध कराएगा,जिससे उनकी समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से संभव होगा। साथ ही,पेमेंट गेटवे,ऐप स्टोर्स और अन्य डिजिटल मध्यस्थों को भी जवाबदेह बनाकर एक व्यापक और सुरक्षित गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जाएगा, जो उपयोगकर्ता हितों की रक्षा सुनिश्चित करेगा।

डिजिटल अनुशासन और जिम्मेदार व्यवहार की स्पष्ट दिशा तय करते हुए ओजीएआई का आगमन परिपक्व और दूरदर्शी सोच का संकेत देता है। अब गेमिंग केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहेगा, बल्कि जिम्मेदारी,संतुलन और सजगता का विषय बनेगा। एडिक्टिव डिजाइन, लूट बॉक्सेस और भ्रामक विज्ञापनों पर कड़े नियंत्रण से उपयोगकर्ताओं को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय वातावरण मिलेगा। ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलने से युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने और सशक्त करियर बनाने के अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि सरकार इसे प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता देकर प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम चला रही है। साथ ही,शैक्षिक गेम्स शिक्षा को रोचक,प्रभावी और सहभागितापूर्ण बनाकर डिजिटल दुनिया के सकारात्मक पक्ष को और अधिक स्पष्ट रूप से सामने लाएंगे।

परिवर्तन की इस व्यापक रूपरेखा के साथ चुनौतियों की परतें भी समान रूप से मौजूद हैं,जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विदेशी सर्वरों से संचालित अवैध प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण स्थापित करना तकनीकी दृष्टि से जटिल कार्य है, जिसमें ओजीएआई आईटी एक्ट के तहत ब्लॉकिंग की सिफारिश कर सकता है। इसके साथ ही, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रभावी समन्वय बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण पहलू रहेगा। छोटे डेवलपर्स के लिए अनुपालन सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है, जिससे नवाचार प्रभावित होने की आशंका है। इसलिए ओजीएआई को लचीली और डेटा-आधारित नीतियां अपनानी होंगी,ताकि नियमन और रचनात्मकता के बीच संतुलन बना रह सके।

इस परिवर्तन की वास्तविक सफलता केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समाज की सक्रिय और जागरूक भागीदारी पर भी समान रूप से निर्भर करेगी। माता-पिता को बच्चों के स्क्रीन टाइम पर सतर्क और संतुलित नियंत्रण रखना होगा,स्कूलों को जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सही दिशा और समझ विकसित करनी होगी,तथा मीडिया को भी इस विषय को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करना होगा। जब समाज इस पहल को सकारात्मक रूप से अपनाएगा, तभी इसका व्यापक और प्रभावी परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ओजीएआई वास्तव में एक सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है, जिसकी सफलता हर नागरिक की सहभागिता से ही सुनिश्चित हो सकती है। जब भविष्य की दिशा तय होती है,तो कुछ तिथियाँ इतिहास में मील का पत्थर बन जाती हैं–1 मई 2026 भी ऐसा ही एक निर्णायक क्षण साबित होगा। ओजीएआई का प्रभावी क्रियान्वयन न केवल युवाओं को लत के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखेगा,बल्कि एक संतुलित, सुरक्षित और जिम्मेदार गेमिंग संस्कृति को भी सुदृढ़ करेगा। यदि यह पहल दूरदर्शिता और सतत प्रयासों के साथ आगे बढ़ती है, तो भारत वैश्विक परिदृश्य पर एक अनुकरणीय मॉडल बन सकता है। यह केवल एक नीति नहीं, बल्कि एक सशक्त संकल्प है–जो डिजिटल भारत को अधिक जिम्मेदार, सुरक्षित और जागरूक राष्ट्र में रूपांतरित करने की क्षमता रखता है।

आचार्य महाश्रमण की निर्गुण-चेतना से विश्व-शांति की नई दिशा

ललित गर्ग
पटपड़गंज,दिल्ली-92

मानव इतिहास के इस अशांत और संक्रमणकालीन दौर में जब विश्व का परिदृश्य युद्ध, हिंसा, आतंकवाद और वैचारिक टकरावों से आच्छादित है,तब शांति,सह-अस्तित्व और मानवीय मूल्यों की पुकार पहले से कहीं अधिक तीव्र हो उठी है। ऐसे समय में आचार्य महाश्रमण एक ऐसे आध्यात्मिक प्रकाशस्तंभ के रूप में उभरते हैं,जिनका चिंतन केवल किसी एक पंथ, सम्प्रदाय या राष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के कल्याण का व्यापक दृष्टिकोण अपने भीतर समेटे हुए है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व 'निर्गुण रंगी चदरिया' की उस अनुभूति को मूर्त करता है,जो गुणों के पार जाकर आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थित होने का संदेश देती है। भगवद्गीता में अर्जुन को दिए गए श्रीकृष्ण के उपदेश 'त्रिगुणातीत बन जा' के अनुरूप आचार्य महाश्रमण का जीवन एक सजीव उदाहरण बनकर सामने आता है। उन्होंने सत्व,रज और तम के बंधनों को पार कर उस निर्गुण अवस्था को साधने का प्रयास किया है,जहाँ व्यक्ति न केवल आत्मबोध को प्राप्त करता है, बल्कि समष्टि के कल्याण का माध्यम भी बन जाता है। उनका यह दृष्टिकोण केवल दार्शनिक विमर्श नहीं,बल्कि व्यवहारिक जीवन में उतरा हुआ सत्य है। उनकी साधना 'सत्य की पूजा' नहीं करती,बल्कि 'सत्य की शल्य-चिकित्सा' करती है अर्थात् वे सत्य को केवल स्वीकार नहीं करते,बल्कि उसकी गहराई में उतरकर उसे परिष्कृत करते हैं।

आचार्य महाश्रमण का जीवन 'रहें भीतर,जीएँ बाहर' के सूत्र पर आधारित है। यह सूत्र आधुनिक जीवन की जटिलताओं में संतुलन स्थापित करने का एक अद्वितीय मार्ग प्रस्तुत करता है। आज का मनुष्य बाहरी उपलब्धियों की दौ में अपने भीतर के शून्य को अनदेखा कर देता है,जिसके परिणामस्वरूप तनाव,असंतोष और हिंसा का जन्म होता है। आचार्य महाश्रमण का चिंतन इस अंतर्विरोध को समाप्त करने का प्रयास करता है। वे सिखाते हैं कि यदि भीतर शांति और संतुलन है, तो बाहर का जीवन स्वतः ही सुव्यवस्थित हो जाता है। यही कारण है कि उनकी साधना केवल आत्मिक उन्नति तक सीमित नहीं रहती,बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी आधार बनती है। उनकी 'अहिंसा यात्रा' आज के समय की एक ऐतिहासिक और युगान्तरकारी पहल है, जो हमें दांडी यात्रा और भूदान आंदोलन की याद दिलाती है। यह यात्रा केवल एक पदयात्रा नहीं,बल्कि विचारों की क्रांति है-एक ऐसी क्रांति,जो हथियारों से नहीं, बल्कि संवाद, संवेदना और संस्कारों से संचालित होती है। देश-विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल चलकर उन्होंने लाखों लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया, उन्हें नशामुक्ति,सदाचार,नैतिकता और अहिंसा के मार्ग पर अग्रसर किया। आज जब विश्व के अनेक

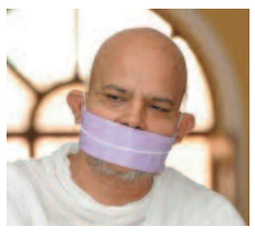

देश युद्ध और आतंकवाद की विभीषिका से जूझ रहे हैं,तब आचार्य महाश्रमण का यह प्रयास एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत करता है-एक ऐसा मार्ग,जहाँ शांति केवल एक आदर्श नहीं,बल्कि एक व्यवहारिक संभावना बन जाती है। उनकी दृष्टि 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को साकार करती है,जहाँ सम्पूर्ण विश्व एक परिवार के रूप में देखा जाता है। वे किसी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, वर्ग या क्षेत्र के आधार पर नहीं,बल्कि उसके भीतर विद्यमान गुणों के आधार पर आंकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल सामाजिक समरसता को बे ावा देता है,बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति और सहयोग की नींव भी रखता है। आज जब पहचान की राजनीति और सांस्कृतिक विभाजन समाज को खंडित कर रहे हैं,तब आचार्य महाश्रमण का यह समन्वयवादी दृष्टिकोण अत्यंत प्रासंगिक हो उठता है।

आचार्य महाश्रमण की सादगी, विनम्रता और अनुशासन उनके व्यक्तित्व की विशिष्ट पहचान हैं। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जैसे महान आचार्यों के सान्निध्य में विकसित उनका जीवन एक ऐसी परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है,जो आत्मानुशासन और सेवा को सर्वोच्च मूल्य मानती है। बाल्यावस्था में ही दीक्षा लेकर उन्होंने जिस तप,त्याग और समर्पण का मार्ग अपनाया,वह आज के भौतिकतावादी युग में एक प्रेरणास्रोत है। उनकी जीवन यात्रा मोहनलाल से मुनि मुदितकुमार, फिर महाश्रमण और अंततः आचार्य बनने तक एक ऐसी साधना गाथा है, जो यह सिद्ध करती है कि आत्मबल और संकल्प से किसी भी ऊँचाई को प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य महाश्रमण की बौद्धिक प्रतिभा भी उतनी ही प्रभावशाली है, जितनी उनकी आध्यात्मिक साधना। उत्तराध्ययन सूत्र और भगवद्गीता जैसे महान ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन कर उन्होंने यह सिद्ध किया है कि सत्य किसी एक परंपरा का एकाधिकार नहीं है। उनके प्रवचनों का संकलन 'सुखी बनो' इस दृष्टि का सशक्त उदाहरण है, जिसमें उन्होंने जीवन को सरल,सार्थक और संतुलित बनाने के सूत्र प्रस्तुत किए हैं। उनका चिंतन आगम,दर्शन, तर्कशास्त्र,मनोविज्ञान और समाजशास्त्र जैसे विविध क्षेत्रों को समाहित करता है,जिससे उनका व्यक्तित्व एक बहुआयामी मनीषी के रूप में उभरता है।

आज के वैश्विक परिदृश्य में, जहाँ युद्ध की विभीषिका और परमाणु हथियारों की होड़ मानव अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी है,वहाँ आचार्य महाश्रमण का 'अहिंसा का शंखनाद' एक जीवनदायी संदेश के रूप में सामने आता है। उनका यह विश्वास कि 'अहिंसा केवल एक सिद्धांत नहीं,बल्कि जीवन जीने की कला है',हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या वास्तव में हिंसा के माध्यम से स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है? उनका उत्तर स्पष्ट है-नहीं। शांति का मार्ग केवल संवाद, सहिष्णुता और करुणा से होकर गुजरता है। उनके प्रयासों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्रतिदिन नई ऊर्जा और संकल्प के साथ वे मानव उत्थान के कार्यों में जुटे रहते हैं। उनकी दिनचर्या, उनका अनुशासन और उनका समर्पण यह दर्शाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है,जो अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करे। उनके नेतृत्व में तेरापंथ धर्मसंघ न केवल संगठित और सशक्त हुआ है,बल्कि उसने समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और नैतिक जागरण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

निश्चित तौर पर जैन धर्म के महान तपस्वी,अनुशासनप्रिय, दूरदर्शी और तेजस्वी आचार्य महाश्रमण के सान्निध्य में आध्यात्मिकता और आधुनिकता का अद्भुत संगम बनी जैन विश्व भारती में इस वर्ष योगक्षेम वर्ष के रूप में एक नया आध्यात्मिक इतिहास रचा जा रहा है, आध्यात्मिक प्रशिक्षण की एक नई परंपरा विकसित की जा रही है। देशभर में विचरण करने वाले साधु-संतों को एक जगह बुलाकर आचार्य महाश्रमण उन्हें अध्यात्म का प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह वास्तव में जैन धर्म का एक अनूठा और संभवतः पहला ऐसा व्यापक प्रयोग है,जिसमें वर्षभर तक साधु-साध्वियों के साथ-साथ श्रावक समाज को भी गहन एवं व्यवस्थित रूप से जैन एवं तेरापंथ दर्शन,अध्यात्म,योग, ध्यान,स्वाध्याय,संयम और जीवन मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आचार्य श्री महाश्रमण की दूरदर्शी सोच,उनका अनुशासन, उनका साधना-प्रधान जीवन और समाज को आध्यात्मिक दिशा देने का उनका प्रयास वास्तव में अद्वितीय है। उन्होंने धर्म को केवल परंपरा तक सीमित नहीं रखा,बल्कि उसे जीवन और समाज से जोड़ा। समय को बांधने की अद्भुत खूबी है उनमें। कम समय में अधिक काम। वह भी इतनी सहजता और निर्भरता से सम्पादित कर लेने की सामर्थ्य,उनकी कार्य व्यस्तता कभी व्यग्रता में नहीं बदलती। यह सब इसीलिए हो सकता है कि उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति निवृत्ति से निथर कर आती है। उनकी क्रियाशीलता आंतरिक स्थिरता स्थितप्रज्ञता से अभिनिःसृत होती है।

आचार्य महाश्रमण का चिंतन एक नए युग का उद्घोष है-एक ऐसा युग,जहाँ विज्ञान और आध्यात्म,भौतिकता और नैतिकता,व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन स्थापित हो सके। वे हमें यह सिखाते हैं कि वास्तविक प्रगति केवल तकनीकी उन्नति से नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों के विकास से संभव है। उनका जीवन और संदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि यदि हम अहिंसा, सत्य,और करुणा के मार्ग पर चलें,तो एक शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व का निर्माण संभव है। अंततः आचार्य महाश्रमण केवल एक धर्मगुरु नहीं,बल्कि एक युगद्रष्टा हैं,जिनकी दृष्टि वर्तमान की सीमाओं को पार कर भविष्य की संभावनाओं को देखती है। उनकी 'निर्गुण चदरिया' हमें यह संदेश देती है कि जब मनुष्य अपने भीतर के गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध चेतना में स्थित हो जाता है, तभी वह सच्चे अर्थों में मानवता की सेवा कर सकता है। आज के युद्धग्रस्त और अशांत विश्व में,उनके विचार और प्रयास एक प्रकाशपुंज की तरह हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की क्षमता रखते हैं।

साधारण जन से असाधारण शासन तक :
पंचायती राज की नई परिभाषा

जड़ों से उठता बदलाव : जब गाँव बनते हैं विकास के निर्माता
सत्ता का नया मानचित्र : पगडंडियों से तय होती विकास की दिशा

कृति आरके जैन
बड़वानी (मप्र)

जब गाँव की धूल भरी पगडंडी पर बैठा किसान निडर होकर अपनी बात रखता है और उसी स्वर से विकास की दिशा आकार लेने लगती है,तब लोकतंत्र अपनी सबसे जीवंत और वास्तविक पहचान में सामने आता है। 24 अप्रैल उस ऐतिहासिक व्यवस्था का प्रतीक बनकर सामने आता है जिसने सत्ता को बड़े दफ्तरों की सीमाओं से बाहर निकालकर गाँव की खुली चौपालों तक पहुँचा दिया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यह संदेश देता है कि भारत की असली शक्ति ऊँची इमारतों में नहीं, बल्कि उन ग्राम सभाओं में बसती है जहाँ लोग अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करते हैं। यह दिन उस सोच का सम्मान है जिसने यह सिद्ध किया कि शासन केवल ऊपर से नहीं चलता,बल्कि नीचे की सक्रिय भागीदारी से और अधिक मजबूत होता है।

1992 में पारित 73वें संविधान संशोधन ने, जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ, ग्रामीण भारत के इतिहास में ऐसा निर्णायक परिवर्तन लेकर आया, जिसने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देकर उन्हें वास्तविक अधिकारों से सशक्त बनाया। इसके बाद गाँव केवल योजनाओं के उपभोक्ता नहीं रहे, बल्कि वे स्वयं निर्णय निर्माण की मुख्य इकाइयाँ बन गए। सड़क निर्माण, जल प्रबंधन, विद्यालय सुधार और विकास योजनाओं की दिशा अब ग्राम सभा में तय होने लगी। यह परिवर्तन केवल प्रशासनिक सुधार नहीं था, बल्कि जनभागीदारी को वास्तविक शक्ति देने वाली व्यवस्था थी। इससे ग्रामीण समाज को अपने संसाधनों और आवश्यकताओं को पहचानने तथा स्वयं निर्णय लेने का अवसर मिला, जिससे विकास अधिक व्यावहारिक और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बन गया।

पंचायती राज व्यवस्था की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है, जिसने ग्रामीण समाज की कार्यशैली को गहराई से बदल दिया है। आरक्षण प्रणाली ने महिलाओं को नेतृत्व के अवसर देकर उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया के केंद्र में स्थापित किया है। आज 14 लाख से अधिक महिलाएँ सरपंच और पंचायत सदस्य के रूप में अपने गाँवों का नेतृत्व कर रही हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यह परिवर्तन केवल पद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सोच में आए व्यापक बदलाव का संकेत है। जहाँ कभी उनकी भूमिका सीमित समझी जाती थी, वहीं अब वही महिलाएँ विकास की दिशा तय कर रही हैं और नए उदाहरण स्थापित कर रही हैं।

डिजिटल क्रांति ने पंचायती राज व्यवस्था को नई पारदर्शिता और गति प्रदान करते हुए उसे अधिक प्रभावशाली बना दिया है। ई-ग्राम स्वराज, ऑनलाइन बजट निगरानी और डिजिटल भुगतान प्रणाली ने पंचायतों के कार्यों को सरल, तेज़ और अधिक जवाबदेह बना दिया है। अब गाँव के लोग अपने मोबाइल फोन पर आसानी से देख सकते हैं कि विकास कार्यों के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई और उसका उपयोग कहाँ किया गया। इससे जानकारी तक पहुँच आसान हुई है और लोगों की भागीदारी में भी वृद्धि हुई है। तकनीक ने दूरी की बाधाओं को समाप्त कर प्रशासन को अधिक तेज़ और सटीक बनाया है। ग्रामीण क्षेत्र अब केवल पारंपरिक व्यवस्था तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे आधुनिक डिजिटल प्रणाली का सक्रिय हिस्सा बन चुके हैं।

उपलब्धियों के साथ-साथ पंचायती राज व्यवस्था के सामने कई गंभीर चुनौतियाँ भी खड़ी हैं, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता।

अदालतों की तारीख

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

बंसीलाल ने जब अपने पड़ोसी पर दीवार गिराने का मुकदमा दर्ज किया था, तब उनके सिर पर काले बाल थे और आंखों में तेज था। आज पैंतालीस साल बाद,जब वे अदालत की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो उनके हाथ में लाठी थी और आंखों में मोतियाबिंद का धुंधलका। जज साहब ने चश्मा ठीक किया और फाइल के पन्ने पलटते हुए बोले, हम्म.. बंसीलाल बनाम रामगुलाम। रामगुलाम का क्या हुआ? वकील ने जवाब दिया, हुजूर, वे तो बीस साल पहले ही स्वर्ग सिधार गए,अब उनका पोता केस लड़ रहा है। जज साहब ने दूसरी तारीख देते हुए कहा, अगली सुनवाई 2045 में होगी, क्योंकि अभी जरूरी केसों की लिस्ट लंबी है। बंसीलाल ने कांपती आवाज में पूछा, हुजूर,क्या तब तक मैं जीवित रहूंगा? जज साहब मुस्कुराए,यह कानून की चिंता नहीं है बंसीलाल यह बायोलॉजी का विषय है। बंसीलाल अदालत के बाहर निकले और पास के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने देखा कि उनकी दीवार तो अब ढहकर मिट्टी बन चुकी है,और वहां एक विशाल मॉल खड़ा हो गया है। वकील साहब पीछे से

आए और बोले, चिंता मत करो बंसीलाल,मैंने आपकी अगली सात पीढ़ियों का वकालतनामा साइन करवा लिया है। न्याय भले ही न मिले,पर तारीख कभी खत्म नहीं होगी। बंसीलाल को अचानक ययाति की याद आई, जिसने अमरता मांगी थी। उन्हें लगा कि भारत में न्याय पाने के लिए अमर होना सबसे पहली शर्त है। वे घर लौटे और अपने पोते को वसीयतनामा थमाया, जिसमें लिखा था– बेटा, दीवार का दुख छोड़ो, बस तारीख का सम्मान बनाए रखना।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

घनी आबादी में बारूद का जखीरा...अंबिकापुर में भीषण आग से हड़कंप

पटाखों के गोदाम में आग...टला बड़ा हादसा-प्रशासन पर उठे सवाल

- रिहायशी इलाके में अवैध पटाखा भंडारण बना खतरा,अंबिकापुर में भीषण आग
- धमाकों से दहला शहर,पटाखा गोदाम में लगी आग ने खोली सिस्टम की पोल
- आग से ज्यादा खतरनाक लापरवाही–अंबिकापुर हादसे ने उठाए कई सवाल
- पटाखों और प्लास्टिक के गोदाम में आग...12 दमकल भी पड़े कम
- हादसा टला, पर चेतावनी बड़ी–घनी आबादी में बारूद का खेल
- अंबिकापुर में आग का कहर,अवैध भंडारण पर प्रशासन कठघरे में...
- धमाकों से गूंजा इलाका,पटाखा गोदाम में भीषण आग से अफरा-तफरी
- रिहायशी इलाके में मौत का सामान,आग के बाद उठे बड़े सवाल

-संवाददाता-
अंबिकापुर/सरगुजा 23 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित एक प्लास्टिक और पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग ने पूरे अंबिकापुर को हिला कर रख दिया, दोपहर के समय लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई, आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोग दूर खड़े होकर ही स्थिति का अंदाजा लगा रहे थे, जबकि काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था,हालांकि राहत की बात यह रही कि इस बड़े हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन आसपास के घरों और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर घनी आबादी के बीच इस तरह पटाखों का अवैध भंडारण कैसे और किसकी अनुमति से किया जा रहा था।

धमाकों से गूंजा इलाका, दहशत में लोग

आग लगने के कुछ ही समय बाद गोदाम में रखे पटाखों में विस्फोट शुरू हो गए। ये धमाके लगातार होते रहे, जिससे पूरा इलाका दहल उठा, लोगों में भय का माहौल बन गया और कई परिवार अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल आए, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार,धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की दीवारें तक कांपती महसूस हो रही थीं, लोग अपने बच्चों और परिवार के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए,स्थिति इतनी भयावह थी कि कुछ देर के लिए ऐसा लगा मानो कोई बड़ा विस्फोटक हादसा हो गया हो।

आग की तीव्रता ने बढ़ाई मुश्किलें- गोदाम में प्लास्टिक और पटाखों का भारी भंडारण होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। प्लास्टिक सामग्री के जलने से आग और अधिक भड़कती गई, वहीं पटाखों के लगातार फटने से स्थिति और भी नियंत्रण से बाहर होती चली गई, आग इतनी भीषण थी कि घटना के कई घंटे बाद तक उस पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। दमकल विभाग के कर्मचारियों को आग बुझाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

दमकल की कई गाड़ियां जुटीं, फिर भी चुनौती बरकरार- घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं, स्थानीय दमकल वाहन सरगुजा संभाग के अन्य जिलों से बुलाए गए वाहन,कुल मिलाकर 12 से अधिक दमकल गाड़ियां,आग बुझाने के प्रयास में जुटी रहीं,इसके बावजूद संकरी गलियों और लगातार हो रहे विस्फोटों के कारण दमकल कर्मियों को मौके तक पहुंचने और प्रभावी तरीके से आग बुझाने में काफी परेशानी हुई, खबर लिखे जाने तक आग पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं पाया जा सका था, हालांकि राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी था।

लाखों की संपत्ति जलकर खाक- गोदाम में रखे प्लास्टिक के होलसेल सामान और पटाखों का भारी स्टॉक आग में पूरी तरह जलकर खाक हो गया,प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपये के नुकसान की बात सामने आ रही है,इसके अलावा आसपास के कुछ घरों को भी आग की चपेट में आने से नुकसान हुआ है।

अवैध भंडारण पर उठे गंभीर सवाल- इस घटना ने सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा कर दिया है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर पटाखों का भंडारण घनी आबादी के बीच कैसे किया जा रहा था,स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गोदाम को लेकर पहले भी शिकायतें की गई थीं, रिहायशी इलाके में बारूद का भंडारण हमेशा खतरा बना हुआ था,लेकिन प्रशासन ने कभी गंभीरता से जांच या कार्रवाई नहीं की यदि ये आरोप सही हैं, तो यह सीधे तौर पर प्रशासनिक उदासीनता और नियमों की अनदेखी को दर्शाता है।

क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी?- घटना के बाद शहर में यह चर्चा तेज हो गई है कि ऐसे गोदामों को हटाना और उनकी जांच करना प्रशासन की जिम्मेदारी है या नहीं, क्या संबंधित विभागों को इसकी जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी,तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? लोगों का यह भी कहना है कि कई बार प्रभावशाली लोगों के कारण नियमों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे आम जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।

आग बुझी या नहीं,सवाल अभी भी जल रहे हैं- अंबिकापुर की यह आग भले ही कुछ समय बाद बुझ जाए, लेकिन इसने जो सवाल खड़े किए हैं, वे अभी भी जल रहे हैं, रिहायशी इलाके में पटाखों का अवैध भंडारण, प्रशासन की निष्क्रियता, और नियमों की अनदेखी ये सभी मुद्दे अब चर्चा के केंद्र में हैं, अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस घटना से कितना सबक लेता है और क्या वास्तव में ऐसे खतरनाक भंडारण पर सख्त कार्रवाई करता है या नहीं, फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि हादसा टल गया, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है।

प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई होगी या नहीं?

इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन वास्तव में जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेगा, अक्सर देखा गया है कि इस तरह की घटनाओं के बाद जांच की बात कही जाती है,लेकिन समय बीतने के साथ मामला ठंडा पड़ जाता है,इस बार लोगों की उम्मीद है कि अवैध भंडारण की जांच हो,दोषियों की पहचान की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए।

हादसा टला...लेकिन चेतावनी गंभीर

हालांकि इस घटना में किसी की जान नहीं गई,लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी, उससे यह साफ है कि यह एक बड़ा हादसा बन सकता था,अगर आग आसपास के घरों में तेजी से फैलती या कोई बड़ा विस्फोट होता, तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी, इस लिहाज से यह घटना एक गंभीर चेतावनी है, जिसे नजरअंदाज करना भविष्य में भारी पड़ सकता है।

संकरा रिहायशी इलाका बना बड़ी चुनौती

जिस स्थान पर यह गोदाम स्थित था,वह घनी आबादी वाला और संकरा इलाका है। यहां बड़ी गाड़ियों का प्रवेश पहले से ही कठिन था,आग लगने के बाद यही स्थिति दमकल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। गली संकरी होने के कारण दमकल की गाड़ियों को अंदर तक पहुंचने में समय लगा,जिससे आग और फैलती गई, यह पहलू भी प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है कि ऐसे संवेदनशील और खतरनाक गोदामों को रिहायशी क्षेत्रों में क्यों संचालित होने दिया गया।

प्रशासन ने कराया क्षेत्र खाली, नुकसान सीमित करने की कोशिश-

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आसपास के घरों को खाली कराया,स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया और क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों को हटवाया गया,ताकि आग फैलने की स्थिति में नुकसान कम से कम हो,कलेक्टर और एसपी स्वयं मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की। प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य आग को फैलने से रोकना और जनहानि से बचाव करना रहा।

रिहायशी एरिया में नहीं होनी चाहिए गोदाम

मौके पर पहुंचे पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि सूचना मिलते ही मैं तत्काल कलेक्टर व एसपी को सूचित किया। सभी जगह से फायर ब्रिगेड मंगाया गया है। आबादी वाले क्षेत्र में पटाखा व गोदाम को लेकर कहा कि सड़कें चौड़ीकरण होनी चाहिए, रिहायशी इलाके में गोदाम होनी ही नहीं चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि गोदाम में आग की घटना हुई है। लगातार बुझाने की कोशिश की जा रही है। आस पास के घरों को खाली करा दिया गया है।

शासकीय कार्य में बाधा डालने वाला बदमाश गिरफ्तार,पटवारी से मारपीट कर चापड़ दिखाकर दी थी धमकी

-संवाददाता-
अंबिकापुर/दरिमा,23 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र में पटवारी कार्यालय में घुसकर शासकीय कार्य में बाधा डालने,पटवारी से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से लोहे का चापड़ और घटना में प्रयुक्त हैरियर वाहन जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार,22 अप्रैल को ग्राम कंठी पटवारी हल्का नंबर 03 में पदस्थ पटवारी अपने कार्यालय में कार्य कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी जितेंद्र कुजूर उर्फ मोनू वहां पहुंचा और आरआई सोहगा का नंबर मांगा। नंबर देने के बाद उसने पटवारी पर दबाव बनाया कि वे अपने मोबाइल से बात कराएं। मना करने पर आरोपी भड़क गया और गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्कों व कुर्सी से मारपीट कर दी। बताया गया कि इसके बाद आरोपी अपनी कार से चापड़ लेकर आया और पटवारी व चौकीदार को दौड़ाकर जान से मारने की धमकी दी। दोनों किसी तरह वहां से भागकर सुरक्षित निकले। मामले की शिकायत पर थाना दरिमा में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के निर्देश पर थाना दरिमा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की और उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी ने घटना करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ते हुए न्यायालय में पेश किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पूर्व से आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने किया 520 लाख रू. से अधिक के नहर-जलाशय जीर्णोद्धार कार्यों का भूमिपूजन

जलाशय और नहर जीर्णोद्धार से बढ़ेगी कृषि उत्पादकता, किसानों की आय में होगी वृद्धि

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ में जल प्रबंधन और ग्रामीण अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज अम्बिकापुर विधानसभा अंतर्गत उदयपुर विकासखंड में 520 लाख रू. से अधिक लागत के दो महत्वपूर्ण नहर-जलाशय जीर्णोद्धार कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें 265.99 लाख की लागत से डांड़गांव जलाशय बांध एवं नहर जीर्णोद्धार तथा 254.34 लाख रू. की लागत से पंडरीडांड़ जलाशय बांध एवं नहर जीर्णोद्धार कार्य शामिल हैं। यह मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की जल-प्रबंधन और अधोसंरचना

विकास को प्राथमिकता देने वाली नीति का सशक्त उदाहरण है। भूमिपूजन के अवसर पर मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि जलाशयों और नहरों के सुदृढ़ीकरण से क्षेत्र की सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे किसानों को वर्षभर पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। अन्नदाताओं को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलने से वे बहुफसली खेती की ओर अग्रसर होंगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ उनकी आय में भी सीधा इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि इस तरह की परियोजनाएं केवल खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य नहीं करतीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने का माध्यम बनती हैं। जलाशयों और नहरों के जीर्णोद्धार से जल संचयन क्षमता बढ़ेगी और भू-जल स्तर में सुधार होगा, जिससे लंबे समय तक सिंचाई की स्थिर व्यवस्था बनी रहेगी। इससे धान के अलावा दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों को भी बढ़ावा मिलेगा, जो कृषि विविधीकरण और बाजार आधारित खेती के लिए महत्वपूर्ण है। इससे किसानों की आय में स्थिरता आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी सहायक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। जल संकट में कमी आने से ग्रामीणों को पेयजल की बेहतर उपलब्धता होगी, वहीं महिलाओं को पानी लाने की कठिनाइयों से राहत मिलेगी। जलस्तर में सुधार और हरियाली बढ़ने से पर्यावरणीय संतुलन भी मजबूत होगा,जो क्षेत्र के समग्र विकास में सहायक सिद्ध होगा।

संलग्नीकरण समाप्त होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका,फेडरेशन ने संयुक्त संचालक से की मुलाकात

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जिला सरगुजा के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को जिला संयोजक कमलेश सोनी के नेतृत्व में संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, सरगुजा संभाग से सौजन्य मुलाकात कर स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों के संलग्नीकरण समाप्त किए जाने से उत्पन्न समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर के 12 मार्च 2026 के आदेश के तहत मूल पदस्थ संस्थाओं से अन्य संस्थाओं में संलग्न समस्त चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों का संलग्नीकरण समाप्त करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद जे.डी. स्वास्थ्य सेवाएं अंबिकापुर एवं सीएमएचओ

सरगुजा द्वारा संबंधित कर्मचारियों को मूल पदस्थापना स्थल के लिए कार्यमुक्त किया गया। फेडरेशन ने कहा कि कर्मचारियों के कार्यमुक्त होने से जिले के विभिन्न अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों के इलाज और कार्यालयीन कार्य प्रभावित होने की संभावना है। इसी स्थिति को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सरगुजा द्वारा शहरी स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में 16 चिकित्सा कर्मियों को पूर्ववत कार्य संपादन के लिए 22 अप्रैल को आदेश जारी किया गया है।

'दैनिक घटती-घटना' की खबर का बड़ा असर केशगवा पंचायत में 3 लाख के गबन मामले में सचिव निलंबित

सरपंच की डीएससी का दुरुपयोग और फर्जी आहरण मामले में जिला पंचायत की बड़ी कार्यवाही

'पंच संघ' के आक्रोश और घटती घटना की खबर के बाद जागा प्रशासन....

-राजन पाण्डेय-

सोनहत/कोरिया,23 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

वनांचल क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार के खिलाफ 'घटती-घटना' द्वारा प्रमुखता से उठाई गई आवाज का बड़ा असर देखने को मिला है,ग्राम पंचायत केशगवा में 15 वें वित्त की राशि के बंदरबांट और सरपंच को धोखे में रखकर 3 लाख रुपये के गबन मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी सचिव श्यामलाल सूर्यवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

धोखे और जालसाजी का हुआ खुलासा

जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि सचिव श्यामलाल सूर्यवंशी ने पद का दुरुपयोग करते हुए सरपंच सोभित राम को विश्वास में लिया और 'प्रिया शाफ्ट' के नाम पर उनकी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हासिल कर ली। जांच रिपोर्ट के अनुसार,ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर सरपंच की यूजर प्रोफाइल में सचिव ने अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर रखा था,जिससे वह बिना सरपंच की जानकारी के ओटीपी और अन्य प्रक्रियाओं को अंजाम देकर राशि आहरण करता रहा।

जांच से बचता रहा सचिव,पर नहीं मिली राहत

निलंबन आदेश (क्रमांक/जि.पं./पंचा.अनु/2026) के मुताबिक,जांच समिति ने सचिव को अपना पक्ष रखने और अभिलेख प्रस्तुत करने के कई अवसर दिए, लेकिन सचिव ने जांच में सहयोग करने के बजाय दूरी बनाए रखी। अंततः सरपंच के डीएससी के गलत उपयोग और वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होने पर उसे छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत दोषी माना गया।

घटती घटना | कोरिया- सूरजपुर समाचार | अम्बिकापुर मंगलवार 21 अप्रैल 2026 | 9

ग्राम पंचायत केशगवा में 15 वें वित्त की राशि का बंदरबांट,सचिव पर 3 लाख के गबन का आरोप

पंच संघ की चेतावनी और मीडिया का दबाव-

विदित हो कि इस मामले को लेकर 'पंच संघ सोनहत' के अध्यक्ष प्रेम सागर तिवारी ने मोर्चा खोल दिया था, उन्होंने आरोप लगाया था कि जांच में पुष्टि के बावजूद कार्यवाही को दबाने की कोशिश की जा रही है। पंच संघ ने 10 दिनों के भीतर एफआईआर न होने पर कलेक्टर कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी थी, 'घटती घटना' ने इस जन सरोकार के मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और निलंबन की गाज गिरी।

निलंबन आदेश की मुख्य बातें...

- निलंबन एवं मुख्यालय सचिव श्यामलाल सूर्यवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय जनपद पंचायत सोनहत निर्धारित किया गया है।
- विभागीय जांच : उपसंचालक (पंचायत) जिला कोरिया को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त कर मामले की औपचारिक विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।
- नई नियुक्तियां केशगवा का प्रभार अब शिवनारायण साहू (सचिव, मधला) और बसवाही का अतिरिक्त प्रभार रामप्रकाश साहू (सचिव, तंजरा) को सौंपा गया है।

सचिवों के दोहरे प्रभार पर रोक सहित बिना प्रभार वाले सचिवों को प्रभार की मांग

इसके साथ ही पंच संघ ने प्रशासन के समक्ष एक और महत्वपूर्ण मांग रखी है,संघ का कहना है कि एक ही सचिव को दो या दो से अधिक पंचायतों का प्रभार दिए जाने से कार्यों में पारदर्शिता की कमी आती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, संघ ने मांग की है कि दागी और वित्तीय अनियमितता में संलिप्त सचिवों को अतिरिक्त प्रभार से तत्काल मुक्त किया जाए। वहीं,जनपद में ऐसे कई सचिव भी मौजूद हैं जिनके पास वर्तमान में कोई पंचायत नहीं है, उन्हें रिक्त पंचायतों की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए ताकि क्षेत्र का विकास बाधित न हो और पंचायतों की मॉनिटरिंग बेहतर ढंग से हो सके।

सचिवों के दोहरे प्रभार पर रोक की मांग...

इसके साथ ही पंच संघ ने प्रशासन के समक्ष एक और महत्वपूर्ण मांग रखी है। संघ का कहना है कि एक ही सचिव को दो या दो से अधिक पंचायतों का प्रभार दिए जाने से कार्यों में पारदर्शिता की कमी आती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है,संघ ने मांग की है कि दागी और वित्तीय अनियमितता में संलिप्त सचिवों को अतिरिक्त प्रभार से तत्काल मुक्त किया जाए। वहीं, जनपद में ऐसे कई सचिव भी मौजूद हैं जिनके पास वर्तमान में कोई पंचायत नहीं है, उन्हें रिक्त पंचायतों की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए ताकि क्षेत्र का विकास बाधित न हो और पंचायतों की मॉनिटरिंग बेहतर ढंग से हो सके।

इनका कहना है

'यह भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी और ग्रामीणों की साझा जीत है। 'मीडिया ने जिस तरह से इस घोटाले को उजागर किया, उससे प्रशासन पर कार्यवाही का दबाव बना, हमारी मांग है कि केवल निलंबन ही नहीं, बल्कि गबन की गई राशि की वसूली और मामले पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। '

प्रेम सागर तिवारी,अध्यक्ष (पंच संघ,सोनहत)

भुगतान रुका,गुस्सा फूटा- अब कारखाने पर ताला पड़ेगा!

4 माह से बकाया, किसानों-मजदूरों का अल्टीमेटम -27 अप्रैल को घेराव तय

-संवाददाता-

प्रतापपुर,23 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

प्रतापपुर विकासखंड में गन्ना किसानों और मजदूरों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। विगत चार माह से भुगतान लंबित होने के कारण आक्रोशित किसानों और श्रमिकों ने 27 अप्रैल 2026 को मां महामाया शक्कर कारखाना का घेराव और तालाबंदी करने का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 11 सुरेश कुमार आयाम के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों और कारखाने में कार्यरत मजदूरों को पिछले चार महीनों से उनका मेहनताना नहीं मिला है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। परिवार के भरण-पोषण से लेकर बच्चों की पढ़ाई और दैनिक जरूरतों तक का संकट गहराता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर 8 अप्रैल 2026 को पहले ही शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें 15 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की गई थी। साथ ही किसानों ने यह भी मांग रखी थी कि कारखाने में गन्ना किसानों द्वारा मनोनीत अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान प्रभावी तरीके से हो सके। लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से किसानों और मजदूरों में भारी असंतोष व्याप्त है। ज्ञापन सौंपने के दौरान नवीन जायसवाल, त्रिभुवन सिंह, मासूम इराकी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस कार्रवाई की जरूरत है। किसानों का कहना है कि समय पर भुगतान नहीं होने से वे कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। कई किसानों ने अपनी फसल उधार लेकर तैयार की थी,लेकिन भुगतान नहीं मिलने से वे आर्थिक संकट में फंस गए हैं। वहीं मजदूरों की स्थिति भी बेहद खराब हो चुकी है,जिनके सामने रोजमर्रा के खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। जिला पंचायत सदस्य सुरेश आयाम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 27 अप्रैल तक बकाया भुगतान नहीं किया गया,तो किसान और मजदूर शांतिपूर्ण तरीके से कारखाने का घेराव कर तालाबंदी करेंगे,जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया,तो यह आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन किसानों और मजदूरों की समस्याओं को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या 27 अप्रैल से पहले कोई ठोस पहल सामने आती है या नहीं।

मनेंद्रगढ़ के पालना घर में बड़ा खेल! कागजों में संचालन जमीनी हकीकत में ताला-लाखों की गड़बड़ी के आरोप

पालना घर योजना पर उठे गंभीर सवाल.....

-संवाददाता-

मनेंद्रगढ़,23 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

शहरी क्षेत्र मनेंद्रगढ़ के वार्ड क्रमांक 1 ब/21 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित 'पालना घर' योजना अब गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है, सूत्रों के अनुसार यह योजना केवल कागजों में संचालित दिखाई जा रही है, जबकि जमीनी स्तर पर यहां कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही, बताया जा रहा है कि जिस पालना घर का उद्देश्य बच्चों की देखरेख और सुविधा सुनिश्चित करना है, वहां न तो नियमित संचालन हो रहा है और न ही बच्चों की उपस्थिति देखने को मिल रही है।

कागजों में चल रहा संचालन,जमीन पर ताला

स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के मुताबिक संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र में पालना घर का संचालन दिखाया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में केंद्र अधिकांश समय बंद रहता है, इस स्थिति ने यह संदेह पैदा कर दिया है कि योजना का क्रियान्वयन केवल दस्तावेजों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि लाभार्थियों तक इसका फायदा नहीं पहुंच रहा।

राशि आहरण पर उठे सवाल- सबसे बड़ा सवाल योजना की राशि को लेकर उठ रहा है, सूत्रों का दावा है कि पालना घर के नाम पर शासन से मिलने वाली राशि का नियमित आहरण किया जा रहा है,जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस गतिविधि नहीं हो रही, ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि लाखों रुपये की राशि में वित्तीय अनियमितता की जा रही है।

परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर की भूमिका संदिग्ध

सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी शशि जायसवाल और संबंधित सेक्टर की सुपरवाइजर की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है,आरोप है कि दोनों की कथित मिलीभगत से योजना की राशि में बंदरबांट किया जा रहा है और शासन की महत्वपूर्ण योजना को केवल कागजों तक सीमित कर दिया गया है।

स्थानीय लोगों में आक्रोश

इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है, लोगों का कहना है कि बच्चों के हित में बनाई गई योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है, उनका आरोप है कि अगर समय रहते जांच नहीं हुई, तो इस तरह की अनियमितताएं और बढ़ सकती हैं।

संपर्क करने पर नहीं मिला जवाब

इस संबंध में जब परियोजना अधिकारी शशि जायसवाल से मोबाइल नंबर 9424263267 पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, इससे पूरे मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर और भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

जांच की मांग और प्रशासन पर सवाल

- क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी?
- क्या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी?
- या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा?

योजना या घोटाला?

मनेंद्रगढ़ के इस पालना घर का मामला केवल एक केंद्र तक सीमित नहीं,बल्कि यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है, यदि आरोप सही हैं, तो यह न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग है, बल्कि बच्चों के अधिकारों के साथ भी खिलवाड़ है, अब नजर प्रशासन की कार्रवाई पर है कि वह इस मामले में क्या कदम उठाता है क्योंकि यहां सवाल केवल एक योजना का नहीं, बल्कि भरोसे का है।

आवास मिला...लेकिन अधूरा : सूरजपुर में गरीबों के सपनों पर 'किस्त' का ताला

प्रतापपुर ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित...मजदूरी भी अटकी-आदिवासी परिवारों पर दोहरी मार

-संवाददाता-

प्रतापपुर,23 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा अंचल में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना जहां हजारों गरीब परिवारों के लिए पक्के मकान का सपना लेकर आई, वहीं सूरजपुर जिले के कई गांवों में यही योजना अब अधूरी उम्मीदों का प्रतीक बनती नजर आ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी प्रतापपुर ब्लॉक के हितग्राहियों को झेलनी पड़ रही है, जहां बड़ी संख्या में गरीब और विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के परिवार इस संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, योजना के तहत उन्हें मकान स्वीकृत तो हुआ, पहली किस्त भी मिली, लेकिन उसके बाद की राशि महीनों से अटकी हुई है। किसी तरह मजदूरी कर या उधार लेकर उन्होंने अपने घरों की दीवारें खड़ी कर दीं और डीपीसी तक निर्माण कार्य पूरा किया, लेकिन दूसरी किस्त नहीं मिलने से अब निर्माण कार्य पूरी तरह ठप पड़ गया है। प्रतापपुर ब्लॉक के कई गांवों में यह स्थिति आम हो गई है। अधूरे मकान खुले में खड़े हैं और परिवार असुरक्षित हालात में रहने को मजबूर हैं। कई जगहों पर दीवारें तो खड़ी हैं, लेकिन छत नहीं होने के कारण लोग फिर से पुराने कच्चे घरों या अस्थायी झोपड़ियों में रहने को विवश हैं।

हितग्राहियों का कहना है कि उन्होंने कई बार जनपद और जिला स्तर के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन तीन माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस लापरवाही ने गरीब परिवारों को गहरे संकट में डाल दिया है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब यह सामने आता है कि इन परिवारों को मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी भी समय पर नहीं मिल रही है। तीन से चार महीने से मजदूरी भुगतान लंबित है, जिससे उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कई परिवारों में खाने तक के लाले पड़ गए हैं और लोग कर्ज लेकर जीवनयापन करने को मजबूर हैं। एक हितग्राही ने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा,'सरकार ने हमें मकान का सपना दिखाया, लेकिन अब बीच मझधार में छोड़ दिया। अगर समय पर पैसा नहीं मिलना था, तो हमें इस स्थिति में क्यों डाला गया?' ग्रामीणों का कहना है कि वे शासन की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनता ने पूरी योजना की गति को प्रभावित कर दिया है। विशेष रूप से प्रतापपुर ब्लॉक में यह समस्या व्यापक रूप से देखने को मिल रही है, जहां अधिकांश हितग्राही परेशान हैं और समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मानसून का खतरा भी सामने है। यदि समय रहते निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, तो अधूरे मकान और भी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिससे गरीब परिवारों की स्थिति और खराब हो जाएगी। अब प्रभावित हितग्राहियों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द दूसरी किस्त जारी की जाए और मनरेगा मजदूरी का भुगतान किया जाए, ताकि वे अपने अधूरे घरों को पूरा कर सकें और सम्मानजनक जीवन जी सकें।

मछुआरों की लापरवाही और बदहाल व्यवस्था से गहराया संकट

अब बहाल हुई जल आपूर्ति,सूरजपुर में 48 घंटे बाद मिली राहत

एनीकेट खुला,शहर प्यासा–अब बहाल हुई सप्लाई,लेकिन सवाल कायम

मछुआरों की लापरवाही से सूखा सूरजपुर,48 घंटे बाद लौटी पानी की राहत

- जल संकट से जूझा शहर,टैंकरों के सहारे बीते दिन–अब सप्लाई शुरू
- पानी बहा,सिस्टम हिला–अब बहाल हुई सप्लाई,जिम्मेदारी पर बहस जारी
- एनीकेट खुला,शहर प्यासा–48 घंटे बाद बहाल हुई जल आपूर्ति,लेकिन व्यवस्था पर बड़े सवाल कायम
- भीषण गर्मी में जल संकट से जूझा सूरजपुर

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,23 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। भीषण गर्मी के बीच सूरजपुर शहर बीते कुछ दिनों तक एक गंभीर पेयजल संकट से जूझता रहा, जिसने न केवल नगर पालिका की जल प्रबंधन व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि बुनियादी संसाधनों की सुरक्षा और निगरानी में जरा सी चूक पूरे शहर को किस तरह संकट में डाल सकती है। नयनपुर एनीकेट का गेट मछुआरों द्वारा खोले जाने से शुरू हुआ यह संकट देखते ही देखते शहरव्यापी समस्या बन गया, टंकियां खाली हो गईं, नलों ने जवाब दे दिया और लोग पानी के लिए इधर-उधर भटकने को मजबूर हो गए। हालांकि अब लगभग 48 घंटे बाद पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

एनीकेट का गेट खुला,टंकियां हुईं खाली

जानकारी के अनुसार, नयनपुर एनीकेट में नगर पालिका द्वारा शहर की जल आपूर्ति के लिए पानी संग्रहित किया गया था, लेकिन मछुआरों ने मछली पकड़ने के उद्देश्य से एनीकेट का गेट खोल दिया, जिससे भारी मात्रा में पानी बह गया, इसका सीधा असर नगर की जल व्यवस्था पर पड़ा–टंकियां तेजी से खाली हो गईं और कई वार्डों में पानी की सप्लाई अचानक बंद हो गई,जहां रोजाना पानी उपलब्ध होता था, वहां अचानक सूखा पड़ गया।

पहले से चरमराई व्यवस्था ने बढ़ाया संकट

एनीकेट की इस घटना ने उस सच्चाई को उजागर कर दिया, जो लंबे समय से शहर में महसूस की जा रही थी, कई वार्डों में पहले से ही अनियमित जल आपूर्ति हो रही थी, कहीं दो-दो दिन तक पानी नहीं पहुंचता था, तो कहीं बिना सूचना सप्लाई बंद कर दी जाती थी, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया, ऐसे में एनीकेट का पानी बहना पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ।

घटती-घटना | कोरिया- सूरजपुर समाचार | अम्बिकापुर शुक्रवार 23 अप्रैल 2026 | 5

मछुआरों की लापरवाही और बदहाल व्यवस्था से सूरजपुर में जल संकट गहराया,पानी के लिए हाहाकार

एनीकेट खुला,टंकियां सूखीं–सूरजपुर में जल संकट चरम पर,मछली के चक्कर में शहर प्यासा...सूरजपुर में पेयजल संकट गहराया

टैंकरों के भरोसे बीते दिन, लेकिन राहत अधूरी

जल संकट के दौरान नगर पालिका ने टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने का प्रयास किया, लेकिन यह व्यवस्था पूरी तरह पर्याप्त नहीं रही, कई क्षेत्रों में टैंकर समय पर नहीं पहुंचे,तो कहीं पानी की मात्रा जरूरत से कम रही,लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ा,महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। कई परिवारों को मजबूरी में पानी खरीदना पड़ा।

जर्जर मोटर और ठेकेदारी व्यवस्था पर सवाल

नगर पालिका से जुड़े सूत्रों के अनुसार,जल आपूर्ति की व्यवस्था पुराने और जर्जर मोटरों पर निर्भर है,जो बार-बार खराब हो जाती हैं, इसके अलावा टैंकर व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है अधिकांश टैंकर ठेकेदारी में संचालित हो रहे हैं और कई टैंकर रखरखाव के अभाव में जर्जर हो चुके हैं। इसके बावजूद हर साल उनके संधारण पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, यह स्थिति संसाधनों के सही उपयोग पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

जनता में नाराजगी,जिम्मेदारों पर उठे सवाल

पानी की समस्या से परेशान नागरिकों ने नगरपालिका के जिम्मेदारों के प्रति नाराजगी जताई, लोगों का कहना है कि एनीकेट जैसे महत्वपूर्ण जल स्रोत की सुरक्षा क्यों नहीं की गई? मछुआरों द्वारा गेट खोलना कैसे संभव हुआ? करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है? शहर में इन सवालों को लेकर आक्रोश साफ नजर आया।

तत्काल पहल से बनी राहत की स्थिति

स्थिति को गंभीरता से लेते हुए नगरपालिका उपाध्यक्ष शैलेश अग्रवाल ने तत्काल पहल की,उन्होंने पोकलेन मशीन मंगवाकर इंटेक वेल के पास पानी एकत्रित कराया और जल आपूर्ति व्यवस्था को पुनः शुरू कराया,इस दौरान पार्षद प्रमोद तायल, भाजपा नेता संजय केजरीवाल तथा नगर पालिका के कर्मचारियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई,उनकी संयुक्त प्रयासों के बाद शहर में पानी की सप्लाई बहाल हो सकी।

48 घंटे बाद लौटी राहत

लगभग दो दिनों तक चले संकट के बाद अब शहर में नलों से पानी आने लगा है, लोगों ने राहत की सांस ली है और दैनिक जीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है, हालांकि, इस दौरान लोगों को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ीं, उसने जल प्रबंधन की कमजोरियों को उजागर कर दिया है।

गर्मी में बढ़ती चुनौती

इस समय तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है, ऐसे में जल प्रबंधन में छोटी सी चूक भी बड़े संकट का कारण बन सकती है, सूरजपुर की यह घटना इसी का उदाहरण है कि लापरवाही और कमजोर व्यवस्था मिलकर कैसे पूरे शहर को संकट में डाल सकती है।

सबक और समाधान की जरूरत

यह जल संकट केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, यह बताता है कि जल स्रोतों की सुरक्षा बेहद जरूरी है, आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना अनिवार्य है और जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है अब जरूरत है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए और भविष्य के लिए ठोस व्यवस्था तैयार की जाए।

राहत मिली,लेकिन सवाल बाकी

सूरजपुर में पानी की सप्लाई भले ही बहाल हो गई हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, अगर समय रहते व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया, तो आने वाले समय में इस तरह का संकट फिर सामने आ सकता है, फिलहाल शहर को राहत जरूर मिली है, लेकिन अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन इस घटना से कितना सबक लेता है।

शिक्षकों के समर्पण से ही सशक्त होगा शिक्षा तंत्र : मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

जिला स्तरीय शिक्षा अलंकरण समारोह में शिक्षकों का सम्मान

-संवाददाता-

सूरजपुर,23 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। जिला मुख्यालय में आयोजित जिला स्तरीय मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुईं, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक भूलन सिंह मरावी उपस्थित रहे, समारोह में जिलेभर के शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों एवं शिक्षा प्रेमियों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। जिला स्तरीय मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकरण समारोह न केवल शिक्षकों के सम्मान का मंच बना, बल्कि शिक्षा के महत्व और उसमें शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित करने का भी एक सशक्त माध्यम साबित हुआ, यह आयोजन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरा।

'शिक्षक समाज के भविष्य निर्माता-मंत्री का संदेश

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि शिक्षक समाज के भविष्य निर्माता होते हैं और उनके समर्पण से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है, उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है और इस आधार को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी शिक्षकों के कंधों पर है, उन्होंने शिक्षकों से नवाचार और लगन के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ही बच्चों का शैक्षणिक स्तर ऊँचाइयों तक पहुंचेगा।

जिले में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा सुधार-

शिक्षकों को नवाचार और गुणवत्ता पर जोर देने की अपील

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है और इस दिशा में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, उन्होंने सम्मानित शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाते हैं और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं।

विधायक का संदेश–पाठ्यक्रम से आगे बढ़ें शिक्षक-

विधायक भूलन सिंह मरावी ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक सीमित संसाधनों के बावजूद उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, जो सराहनीय है, उन्होंने कहा कि शिक्षक केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रहें, बल्कि बच्चों को नैतिक शिक्षा, अनुशासन और जीवन कौशल से भी जोड़ें, ताकि वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें।

कार्यक्रम के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले में शिक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रगति पर प्रकाश डाला, उन्होंने बताया कि शिक्षकों के निरंतर प्रयास और प्रशासन के मार्गदर्शन से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, नवाचार, नियमित मूल्यांकन और विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सम्मान समारोह बना प्रेरणा का माध्यम

समारोह के दौरान उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिससे पूरे वातावरण में उत्साह और गर्व का माहौल बना रहा,उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गूंज के साथ शिक्षकों के कार्यों की सराहना की, सम्मान प्राप्त करने वाले शिक्षकों के चेहरे पर आत्मसंतोष और गर्व स्पष्ट दिखाई दे रहा था।

आभार और समापन

कार्यक्रम के अंत में सहायक संचालक रविंद्र सिंह देव ने सभी अतिथियों,जनप्रतिनिधियों और उपस्थित शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करते हैं और शिक्षकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

गणमान्य अतिथियों की रही उपस्थिति

इस अवसर पर मुरली मनोहर सोनी,अजय गोयल,पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश यादव, नगर पंचायत उपाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह चौहान, हरिश राजवाड़े, श्री दीपक गुप्ता, कैलाश सिदार, रवि शंकर बउवा, रितेश जायसवाल, सतीश तिवारी, मनी बग्गा, श्री सत्यनारायण जायसवाल, श्यामू साहू, श्रीमती अनीता सहित अन्य जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद् और बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।

दिव्या सिंह सिसोदिया की मांग

सरगुजा कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

ग्राम चठिरमा को मिलेगा राष्ट्रीय स्तर का खेल केंद्र, क्रिकेट मैदान और अकादमी से बनेगा युवाओं का सुनहरा भविष्य

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,23 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। सरगुजा जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक-1 की सदस्य दिव्या सिंह सिसोदिया ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ग्राम चठिरमा में क्रिकेट मैदान एवं अकादमी निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने एवं समस्त प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करते हुए विकास कार्य प्रारंभ कराने की मांग रखी है। जिला पंचायत सदस्य दिव्या सिंह सिसोदिया ने ज्ञापन के माध्यम से सरगुजा कलेक्टर को अवगत कराया है कि ग्राम चठिरमा में प्लॉट नंबर 344, 345 एवं 346 का कुल 3.730 हेक्टेयर भूमि है,जिसमें क्रिकेट मैदान एवं अकादमी का निर्माण कराए जाने से क्षेत्र के बच्चों एवं युवाओं का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। श्रीमती सिसोदिया ने कहा है कि इस क्षेत्र में खेल अधोसंरचना का निर्माण न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करेगा,बल्कि इससे क्षेत्र में खेल संस्कृति और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि क्रिकेट संघ ने उक्त कार्य हेतु निर्धारित राशि 49,79,550/- की सहमति प्रदान कर दी है,तथा जन भावना के अनुरूप इस परियोजना को प्राथमिकता देना आवश्यक है। ज्ञापन में भूमि आवंटन, नामांतरण तथा निर्माण हेतु सभी अनुमतियां तत्काल पूर्ण करने का अनुरोध किया गया है।

देर रात बारात में डीजे बजाना पड़ा भारी पुलिस ने वाहन समेत डीजे किया जब्त

-संवाददाता-

बलरामपुर,23 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। देर रात्रि बारात में तेज आवाज में डीजे बजाना संचालकों को महंगा पड़ गया। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोलाहल अधिनियम के तहत डीजे सिस्टम और पिकअप वाहन जब्त कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बलरामपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जुड़निया पारा में श्यामाचरण यादव के घर राजपुर क्षेत्र से बारात आई हुई थी। इस दौरान देर रात करीब 11:30 बजे बिना किसी वैध अनुमति के डीजे बजाया जा रहा

था। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। जांच के दौरान चंद्र कुमार रजक पिता मांझी राम एवं जय कुमार रजक पिता मांझी राम, दोनों निवासी ग्राम कुन्दी खुर्द थाना राजपुर,जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, द्वारा बिना अनुमति डीजे संचालन करना पाया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 3, 4, 5(1)/15 के तहत मामला दर्ज करते हुए घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन क्रमांक यूपी 64 एटी 0574 तथा डीजे सिस्टम जब्त कर लिया। पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक शांति भंग करने और बिना अनुमति तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

ईश्तहार

रा0प्र0क्र0 /अ-6/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अमर अग्रवाल आ स्व. विजय कुमार अग्रवाल, उम्र 35 वर्ष, जाति-अग्रवाल, निवासी मायापुर अम्बिकापुर के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदक एवं अनावेदकगण 01 से 03 विकाश अग्रवाल अन्य दो के पिता तथा अना0क0 4 हेमलता अग्रवाल के पति विजय कुमार अग्रवाल आ. स्व. मोती लाल अग्रवाल के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर मोहल्ला मायापुर शीट नं. 03 स्थित नजूल भूमि खसरा नं. 1598 /5, 1598 / 27 रकबा क्रमशः 871.5, 594 वर्गफीट भूमि है। भूधारक विजय कुमार अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 29.12.2024 को हो गई है। अतः भूधारक की मृत्यु हो जाने उपरांत उक्त भूमि से उनका नाम विलोपित कर स्वयं सहित अनावेदकगण के नाम से फौति नामांतरण किये जाने हेतु आवेदक द्वारा मृत्तक भूधारक के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 05 05/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा / अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 21/04/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

नाम परिवर्तन सूचना

मैं बिमला दुबे पत्नी स्वर्गीय हरिशरण दुबे ग्राम सेमरा खुर्द ,तहसील प्रतापपुर ,जिला सूरजपुर की हूँ यह ईश्तहार दर्ज कराना चाहती हूं कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश विमला अंकित हो गया है जिसे सुधार कर बिमला दूबे पढ़ा जाए । एवं मेरे सभी शासकीय व अशासकीय कार्यों में बिमला दूबे के नाम से जाना व पहचाना जाए । इस संबंध में मैं ईश्तहार प्रकाशन करा रही हूं । जिस किसी को आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर अपना आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी प्रतापपुर के समक्ष दर्ज करा सकता है। बाद में आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आवेदिका
विमला दुबे
पत्नी स्वर्गीय हरिशरण दुबे
ग्राम सेमरा खुर्द ,तहसील प्रतापपुर
,जिला सूरजपुर,छ.ग.

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा0प्र0क्र0 /अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक आनंद कुमार सिन्हा पिता गोपाल प्रसाद सिन्हा निवासी सेक्टर 29 - ए, मकान नंबर 408 थाना तहसील जिला चंडीगढ के द्वारा ग्राम फुन्दुरडिहारी स्थित खसरा नंबर 229 / 28 रकबा 0.034 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखो में वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 11.05.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः- 16/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन. पदमुद्रा से जारी ।

सील

तहसीलदार
अंबिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार लखनपुर, जिला-सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

लखनपुर दिनाँक 15/4/26

प्रति,
समस्त ग्रामवासी
ग्राम- सलका
तहसील-लखनपुर

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक बनारसी सिंह आ0 रूप साय निवासी ग्राम सलका तहसील लखनपुर के द्वारा अपने (माता) स्व0 भूईरी सिंह की मृत्यु दिनांक 1/1/2014 को हो जाने से (जन्म / मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) एवं छ0ग0 जन्म मृत्यु रिज0 नियम 2001 के नियम 9 (3) के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जिस पर दिनांक 29/4/2026 को सूनवाई की जानी है।

आवेदक/आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेशी तिथि 29/ 04/ 2026 के पूर्व इस न्यायालय में आपत्ति पेश कर सकता है। नियत दिनाँक के पश्चात प्राप्त होने वाले दाव आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

सील

तहसीलदार
लखनपुर,सरगुजा

CMYK

3.60 करोड़ के पुल में तेजी...15 लाख का रपटा अब भी अधूरा-गोबरी नदी पर विकास की दो रफ्तार

पुल टूटा 7 महीने से...रपटा फाइलों में-ठेकेदार बड़े काम में व्यस्त,छोटा काम उपेक्षित

- गोबरी नदी : करोड़ों का निर्माण जारी,जरूरी राहत कार्य ठप्प–जनता जोखिम में
- गोबरी नदी पर विकास की दो तस्वीरें : एक तेज...एक ठप्प

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर/कोरिया,23 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। गोबरी नदी पर चल रहे निर्माण कार्यों ने प्रशासनिक प्राथमिकताओं,ठेकेदारी व्यवस्था और जमीनी जरूरतों के बीच गहरे अंतर को उजागर कर दिया है,एक ओर जहां बिरमताल से उमेशपुर मार्ग पर लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से स्थायी पुल का निर्माण कार्य तेज गति से जारी है,वहीं दूसरी ओर उसी नदी पर पहले से टूटा हुआ पुल और उसके विकल्प के रूप में प्रस्तावित 15 लाख रुपये का रपटा पुल अब तक शुरू भी नहीं हो पाया है, स्थिति की विडंबना यह है कि दोनों कार्यों की जिम्मेदारी एक ही ठेकेदार के पास है,लेकिन उसकी प्राथमिकता स्पष्ट रूप से बड़े बजट वाले प्रोजेक्ट पर केंद्रित दिखाई दे रही है,इसका सीधा असर उन हजारों ग्रामीणों पर पड़ रहा है,जिनके लिए रपटा पुल रोजमर्रा के जीवन की जरूरत बन चुका है।

एक ही नदी, दो परियोजनाएं प्राथमिकता में फर्क क्यों?

गोबरी नदी पर दो अलग-अलग परियोजनाएं चल रही हैं पहली,एक स्थायी पुल जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है और जिसकी लागत करोड़ों में है, दूसरी,एक अस्थायी लेकिन तत्काल राहत देने वाला रपटा पुल, जिसकी लागत अपेक्षाकृत बहुत कम है,हालांकि,जमीनी हकीकत यह है कि स्थायी पुल का निर्माण जहां गति पकड़ चुका है, वहीं रपटा पुल का कार्य फाइलों और औपचारिकताओं में उलझा हुआ है,सूत्रों के अनुसार,रपटा पुल का काम उसी ठेकेदार को दिया गया, जिसने प्रारंभिक स्तर पर नदी में मिट्टी भराव का कार्य किया था। यह भी कहा जा रहा है कि यह कार्य उसे लगभग 'उपहार' के रूप में सौंपा गया। इसके बावजूद,कार्य प्रारंभ न होना कई सवाल खड़े करता है क्या छोटे कार्यों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या आर्थिक लाभ के आधार पर प्राथमिकताएं तय हो रही हैं?

7 महीने से टूटा पुल जमीनी हकीकत जस की तस

गोबरी नदी पर बना पुराना पुल पिछले लगभग 7 महीनों से क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा हुआ है। यह पुल डुमरिया से राष्ट्रीय राजमार्ग 43 (एनएच-43) होते हुए शिवप्रसाद नगर को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग था, इसके टूटने के बाद से दो जिलों के बीच सीधा संपर्क बाधित हो गया है,व्यापार और परिवहन गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, ग्रामीणों को लंबा और महंगा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ रहा है,शुरुआत में प्रशासन ने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था और स्थायी समाधान का भरोसा दिया था,स्थायी पुल को बजट में शामिल करने की बात भी कही गई, लेकिन यह योजना अब तक जमीन पर नहीं उतर पाई है।

रपटा पुलः स्वीकृति,टेंडर, ठेकेदार–फिर भी काम शुरू नहीं

रपटा पुल के लिए लगभग 15 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है,टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है,ठेकेदार का चयन भी हो चुका है, इसके बावजूद,निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है,स्थानीय सूत्रों के अनुसार, ठेकेदार कार्य शुरू करने के लिए मंत्री और विधायक के भूमिपूजन कार्यक्रम का इंतजार कर रहा है,यह स्थिति विकास कार्यों की प्राथमिकता पर गंभीर सवाल खड़े करती है, क्या अब जरूरी काम भी राजनीतिक कार्यक्रमों के बिना शुरू नहीं हो सकते?

ग्रामीणों का संघर्ष, हर दिन जोखिम भरा सफर

पुल के अभाव में स्थानीय लोगों की जिंदगी बेहद कठिन हो गई है,स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, गर्भवती महिलाओं और मरीजों को अस्पताल ले जाना चुनौती बन गया है,किसानों और मजदूरों के काम पर सीधा असर पड़ रहा है, हल्की बारिश में भी नदी का जलस्तर बढ़ते ही आवागमन पूरी तरह ठप्प हो जाता है, ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या अब उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन गई है, लेकिन समाधान अभी भी दूर नजर आता है।

हल्की बारिश में भी रास्ता बंद–बढ़ता खतरा

गोबरी नदी में जलस्तर बढ़ते ही स्थिति और गंभीर हो जाती है, लोग नदी पार करने से कतराने लगते हैं,कई बार बीच रास्ते में फंस जाते हैं, दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है,बरसात के मौसम में यह समस्या विकराल रूप ले सकती है। यदि समय रहते रपटा पुल नहीं बना,तो पूरा क्षेत्र संपर्कहीन हो सकता है।

जनसहयोग से शुरुआत, लेकिन अधूरा प्रयास

पुल टूटने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने स्वयं आगे आकर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की,उन्होंने चंदा एकत्र किया और श्रमदान के जरिए रपटा पुल बनाने का कार्य शुरू किया, कुछ हद तक काम भी हुआ, लेकिन यह प्रयास अधूरा रह गया, जैसे ही मामला प्रशासनिक स्तर पर पहुंचा, जनसहयोग की पहल फाइलों में दब गई।

पूर्व चेतावनियां नजरअंदाज अब संकट गहराया

जुलाई और अगस्त 2025 में प्रकाशित खबरों में इस पुल की स्थिति और निर्माण गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे,इन खबरों में स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया, तो स्थिति गंभीर हो सकती है,इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई निरीक्षण के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ,चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया आज 7 महीने बाद वही आशंकाएं हकीकत बन चुकी हैं।

विभागीय उदासीनताः जिम्मेदारी से दूरी-

इस पूरे मामले में सेतु विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है,ठेकेदार पर कोई दबाव नहीं, कार्य प्रारंभ कराने में देरी,अधिकारियों का संपर्क से बचना,स्थानीय लोगों का आरोप है कि संबंधित अधिकारी फोन तक उठाने से बच रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस समस्या को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है।

निरीक्षण और आश्वासनः जमीनी असर नहीं...

इस दौरान कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया,हर बार समाधान का आश्वासन दिया गया,लेकिन वास्तविकता में कोई ठोस कार्य शुरू नहीं हुआ,यह स्थिति दर्शाती है कि प्रशासनिक स्तर पर निर्देश और क्रियान्वयन के बीच बड़ा अंतर है।

आगामी मानसून में संकट और गहराने की आशंका

बरसात का मौसम नजदीक है,यदि जल्द ही रपटा पुल का निर्माण नहीं हुआ, तो आवागमन पूरी तरह ठप हो सकता है ग्रामीणों की परेशानी कई गुना बढ़ सकती है,आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं यह केवल एक पुल का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की जीवनरेखा का सवाल है।

जनता के सवाल की जवाबदेही कौन तय करेगा?

- जब बजट स्वीकृत है,तो काम क्यों नहीं शुरू हुआ?
- एक ही ठेकेदार के पास दोनों काम क्यों दिए गए?
- छोटे लेकिन जरूरी कार्य को प्राथमिकता क्यों नहीं मिली?
- क्या प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से ले रहा है?

विकास का संतुलन जरूरी

गोबरी नदी का यह मामला केवल एक निर्माण कार्य की देरी नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि विकास की प्राथमिकताएं किस तरह असंतुलित हो सकती हैं,एक ओर करोड़ों का पुल बन रहा है, जो भविष्य के लिए जरूरी है,लेकिन दूसरी ओर वर्तमान की जरूरत रपटा पुल अब भी अधूरा है,जब तक तत्काल जरूरतों और दीर्घकालिक योजनाओं के बीच संतुलन नहीं बनाया जाएगा, तब तक ऐसी समस्याएं बार-बार सामने आती रहेंगी,अब यह देखना बाकी है कि प्रशासन और जिम्मेदार विभाग इस मामले में कब तक ठोस कदम उठाते हैं या फिर यह पुल भी लंबे समय तक केवल फाइलों और घोषणाओं में ही बना रहेगा।

5.51 लाख के राशन गबन में सोसायटी संचालिका गिरफ्तार

जांच में 139 क्विंटल चावल की कमी, कोतवाली पुलिस की कार्रवाई

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,23 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। शासकीय राशन गबन के मामले में कोतवाली पुलिस ने सोसायटी संचालिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर करीब 5 लाख 51 हजार रुपए के गबन का आरोप है। जानकारी के अनुसार, खाद्य विभाग के अधिकारी शिव कुमार मिश्रा ने 11 मार्च को कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में उचित मूल्य दुकान क्रमांक 391001032, महामाया वार्ड में 139.49 क्विंटल चावल का व्यपवर्तन पाया गया, जिसकी कीमत लगभग 5,51,112 रुपए आंकी गई। दुकान का संचालन मार्च 2015 से समवृद्ध स्वयं सहायता समूह, दरीपारा द्वारा किया जा रहा था। इसकी अध्यक्ष शोभा सिंह विक्रेता के रूप में कार्यरत थीं। जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 316(5) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। साक्ष्य मिलने पर शोभा सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

पुलिस टीम की भूमिका पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, उप निरीक्षक के.के. यादव, सहायक उप निरीक्षक विवेक पांडेय, महिला आरक्षक किरण अमलावती, आरक्षक लालभुवन व दीपक पांडेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

ग्रामीण ने जंगल में फांसी लगाकर की आत्महत्या

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,23 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। अंबिकापुर. सकालो जंगल में जाकर एक ग्रामीण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में गांधीनगर पुलिस ने मर्ग कायम किया है। जानकारी के अनुसार दुखन कोरिया उम्र 50 वर्ष गांधीनगर थाना क्षेत्र के आसडांड़ का रहने वाला था। वह बुधवार की सुबह 7 बजे घर से निकला था और सकालो जंगल में जाकर फांसी लगा ली थी। फॉरेस्ट गार्ड ने देखा तो घटना की जानकारी परिजन को दी। सूचना पर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। फिलहाल पुलिस मामले में मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।

एसीबी की कार्रवाई के बाद सूरजपुर में राजस्व विभाग में बड़ी सर्जरी-100 से ज्यादा पटवारियों का तबादला

रिश्वतखोरी के मामलों से घिरा सूरजपुर का राजस्व तंत्र...

-संवाददाता-

सूरजपुर,23 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। पिछले डेढ़ साल में सूरजपुर जिले का राजस्व विभाग लगातार भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों से घिरा रहा है, एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की लगातार कार्रवाई में कई पटवारी रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े गए, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए, आम लोगों को अपने ही काम के लिए अवैध पैसे देने की मजबूरी ने इस समस्या को और उजागर किया।

कार्यालय कलेक्टर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

एसीबी की कार्रवाई से बढ़ा प्रशासनिक दबाव

जिले में एक के बाद एक सामने आए मामलों ने प्रशासन को कठघरे में खड़ा कर दिया, एसीबी द्वारा की गई कार्रवाई ने यह साफ कर दिया कि जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार गहराई तक फैला हुआ है, इन घटनाओं के बाद जिला प्रशासन पर सख्त कदम उठाने का दबाव बढ़ता गया और व्यवस्था सुधार की आवश्यकता महसूस की गई।

कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई तबादलों की 'सर्जरी'

इसी परिप्रेक्ष्य में सूरजपुर कलेक्टर ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए राजस्व विभाग में व्यापक स्तर पर तबादले किए, 17 अप्रैल 2026 को जारी आदेश में जिले के विभिन्न तहसीलों सूरजपुर, प्रतापपुर, रामानुजनगर, प्रेमनगर, ओड़गी, भैयाथान, भटगांव और लटोरी–में पदस्थ 100 से अधिक पटवारियों को स्थानांतरित किया गया, यह तबादला प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया बताया गया है, लेकिन इसके पीछे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की मंशा भी साफ दिखाई देती है।

लंबे समय से जमे पटवारियों पर चला डंडा- सूत्रों के अनुसार, कई पटवारी वर्षों से एक ही हल्के में पदस्थ थे, जिससे स्थानीय स्तर पर उनका प्रभाव बढ़ गया था, यही स्थिति कई मामलों में भ्रष्टाचार की वजह बन रही थी, तबादलों के जरिए प्रशासन ने इस जमे हुए नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की है, ताकि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जा सके और जवाबदेही तय हो सके।

भ्रष्टाचार पर अंकुश की कोशिश

हालांकि आदेश में तबादलों को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताया गया है, लेकिन जिस समय यह निर्णय लिया गया है, वह अपने आप में संकेत देता है कि यह कदम रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाने की दिशा में उठाया गया है, एसीबी की लगातार कार्रवाई के बाद यह संदेश देना जरूरी हो गया था कि प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है।

जनता को राहत की उम्मीद

इस बड़े पैमाने पर हुए फेरबदल से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, लोगों का मानना है कि नए स्थानों पर पदस्थ होने से अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी, पुराने संबंध और प्रभाव खत्म होंगे, और भ्रष्टाचार की घटनाओं में कमी आ सकती है, हालांकि यह उम्मीद तभी पूरी होगी जब निगरानी और कार्रवाई की प्रक्रिया भी मजबूत होगी।

सिर्फ तबादला नहीं, व्यवस्था सुधार की जरूरत- विशेषज्ञों का मानना है कि केवल तबादला ही भ्रष्टाचार का स्थायी समाधान नहीं है, जरूरत इस बात की है कि शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हो, निगरानी तंत्र मजबूत किया जाए, और पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनाई जाए, तभी इस तरह के कदमों का वास्तविक लाभ जनता तक पहुंच पाएगा।

प्रशासन के सामने अगली चुनौती- तबादले के बाद अब प्रशासन के सामने यह चुनौती है कि वह नए सिरे से व्यवस्था को पटरी पर लाए, यदि निगरानी में ढिलाई बरती गई, तो पुरानी समस्याएं फिर से सामने आ सकती हैं, इसलिए यह जरूरी है कि इस कार्रवाई के बाद लगातार मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय की जाए।

सख्त संदेश, अब असर का इंतजार- सूरजपुर में राजस्व विभाग में किया गया यह बड़ा फेरबदल एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एसीबी की कार्रवाई के बाद कलेक्टर द्वारा उठाया गया यह कदम प्रशासन की सक्रियता को दर्शाता है, लेकिन इसका वास्तविक असर जमीनी स्तर पर ही दिखाई देगा, फिलहाल यह कहा जा सकता है कि व्यवस्था में 'सर्जरी' हो चुकी है, अब इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने का इंतजार है।

कोई 93 तो कोई 97 पर्सेंट...10 और 12वीं में टॉपर रहीं बॉलीवुड की ये 10 हसीनाएं

आज यूपी बोर्ड के 10 वीं और 12 वीं की परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा हुई। इस खास मौके पर चलिए जानते हैं उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में जो 10 वीं और 12 वीं में टॉपर रहीं।

23 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। अब बात जब पढ़ाई-लिखाई की हो और बॉलीवुड सितारों का नाम उसमें न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बॉलीवुड सितारों की पढ़ाई-लिखाई को लेकर फैंस के मन में अक्सर कई सवाल उठते हैं।चूंकि आज यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट सामने आए हैं, तो चलिए आपको उन अभिनेत्रियों के नाम बताते हैं, जिन्होंने अपने समय में क्लास में सबसे ज्यादा परसेंटेज हासिल किए थे:-

अनुष्का शर्मा

अनुष्का शर्मा का नाम हमने सबसे ऊपर इसलिए लिया है, क्योंकि वह पढ़ाई में काफी होशियार थीं। अनुष्का ने अपनी शुरुआती पढ़ाई आर्मी स्कूल,बेंगलुरु से की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,वह अपने स्कूल की टॉपर रही हैं और उन्होंने 10 वीं की बोर्ड परीक्षा 93 प्रतिशत अंकों के साथ पास की थी।

प्रियंका चोपड़ा

होशियार स्टूडेंट्स की लिस्ट में ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा का नाम भी शामिल है। प्रियंका ने अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान कुछ साल अमेरिका के बोस्टन (न्यूटन नॉर्थ हाई स्कूल, मैसाचुसेट्स) में भी बिताए थे। बाद में उन्होंने भारत लौटकर पढ़ाई पूरी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने 10वीं की परीक्षा में 71 प्रतिशत और 12 वीं में 65 प्रतिशत अंक हासिल किए थे।

परिणीति चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा की कजिन सिस्टर और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की पत्नी,एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी पढ़ाई में बहुत होशियार रही हैं। उन्होंने 12 वीं की परीक्षा में न केवल 97 प्रतिशत स्कोर प्राप्त किया था, बल्कि वह अर्थशास्त्र में ऑल इंडिया टॉपर भी रही थीं।

उर्वशी रौतेला

उर्वशी रौतेला भले ही उम्मीदों के मुताबिक बॉलीवुड में अपनी जगह मजबूत न कर पाई हों, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत ही मेधावी रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक,उर्वशी ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, कोटद्वार से अपनी स्कूलिंग पूरी की है। 12 वीं बोर्ड में उन्होंने शानदार 97 प्रतिशत अंक हासिल किए थे।

कृति सेनन

कृति सेनन हिंदी फिल्मों की सबसे पढ़ाकू एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं। उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज दोनों ही समय में काफी अच्छे नंबर हासिल किए। दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ीं कृति के 10वीं बोर्ड में 90 प्रतिशत आए थे और 12वीं में भी वह फर्स्ट डिवीजन से पास हुई थीं। उन्होंने 12वीं के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है।

आलिया भट्ट

बॉलीवुड में कदम रखते ही आलिया भट्ट की जनरल नॉलेज का भले ही कितना भी मजाक उड़ा हो, लेकिन अपने स्कूल के समय में वह पढ़ने में काफी अच्छी थीं। आलिया ने मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से पढ़ाई की थी। उन्होंने 10 वीं की बोर्ड परीक्षा में 71 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। हालांकि, फिल्मों में ब्रेक मिलने के कारण एक्ट्रेस ने 12 वीं पूरी करने से पहले ही बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी।

यामी गौतम

अपने समय में होशियार बच्चों में शुमार रहीं यामी गौतम स्कूल के दिनों में पढ़ाई में काफी अच्छी थीं। उन्होंने चंडीगढ़ के यादविंद्र पब्लिक स्कूल से अपनी 10वीं और 12 वीं की परीक्षा पास की। 10 वीं में उनकी परसेंटेज 75 प्रतिशत थी।

भूमि पेडनेकर

करियर हो या फिर पढ़ाई,भूमि पेडनेकर को चुनौतियां स्वीकार करना कितना पसंद है,इस बात का अंदाजा फैंस को उनके 10 वीं बोर्ड के मार्क्स से हो जाएगा। मुंबई के जुहू स्थित आर्य विद्या मंदिर से पढ़ीं भूमि को 10 वीं की परीक्षा में 78 प्रतिशत अंक मिले थे।

जाह्नवी कपूर

जाह्नवी कपूर को उनकी एक्टिंग के लिए भले ही कितना भी ट्रोल किया जाए, लेकिन जब आप उनके बोर्ड के नंबर्स सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। धड़क एक्ट्रेस पढ़ाई में काफी होशियार रही हैं। 10 वीं की परीक्षा में जहां जाह्नवी के 84 प्रतिशत आए थे, तो वहीं 12वीं उन्होंने 86 प्रतिशत से पास की थी।

श्रद्धा कपूर

बॉलीवुड की स्त्री जितनी स्वीट हैं,उतनी ही होशियार भी हैं। मुंबई की रहने वालीं श्रद्धा कपूर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जमनाबाई नरसी स्कूल से की थी। 10 वीं में जहां श्रद्धा के कुल 70 प्रतिशत आए थे, तो वहीं उन्होंने 12 वीं में जबरदस्त मेहनत की और 95 प्रतिशत अंक हासिल किए थे।

रिलीज के लिए तरस रही हैं सुनील शेट्टी की 33 फिल्में

ऐश्वर्या राय संग बनते-बनते रह गई जोड़ी

दमदार अभिनेता सुनील शेट्टी के करियर की 33 फिल्में ऐसी रही थीं, जो अब तक सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो सकीं। बॉलीवुड के दमदार अभिनेताओं के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें सुनील शेट्टी का नाम जरूर शामिल होता है। अपने बेहतरीन फिल्म करियर में सुनील ने कई शानदार मूवीज के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। लेकिन आपके ये जानकारी होगी कि एक्टर की 33 फिल्में ऐसी रही हैं,जिनकी घोषणा तो हुई, पर वे सिनेमाघरों में कभी भी रिलीज नहीं हो सकीं। इनमें कुछ फिल्में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के साथ भी बनने वालीं थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि सुनील शेटेटी की कौन सी मूवीज कभी भी रिलीज नहीं हो सकीं।

33 फिल्में नहीं हुईं रिलीज

साल 1992 में आई फिल्म बलवान से बतौर अभिनेता सुनील शेट्टी ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया था। हालांकि, इससे पहले सुनील की एक फिल्म आरजू आने वाली थी, जो लगभग बनकर तैयार हो गई थी,लेकिन बाद में ठंडे बस्ते में चली गई। एनडीटीवी की खबर के अनुसार इसी तरह से सुनील शेट्टी

की टोटल फिल्में डिब्बाबंद हो गईं। आइए उनकी लिस्ट को यहां चेक करते हैं- इस तरह से सुनील शेट्टी की सभी फिल्में अब तक सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तरस रही हैं। हालांकि, इसके बावजूद 3 दशक के फिल्मी करियर में सुनील ने बतौर अभिनेता 100 से अधिक मूवीज में काम किया है और अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी है।

ऐश्वर्या राय के साथ बनने वाली थीं ये मूवीज

इन 33 मूवीज में से 2 फिल्में ऐसी थीं, जिनमें सुनील शेट्टी और ऐश्वर्या राय की जोड़ी बनने वाली थी। उन फिल्मों में राधेश्याम सीता राम और हम पंछी एक डाल के नाम शामिल थे। हालांकि,सुनील साल 2004 में ऐश्वर्या राय की आई क्यों हो गया ना और 2006 में कल्ट मूवी उमराव जान में नजर आ चुके हैं।

सुनील शेट्टी की अगली फिल्म

गौर किया जाए सुनील शेट्टी की अपकमिंग फिल्म की तरफ तो उसमें वेलकम टू द जंगल का नाम शामिल है। इस मल्टी स्टारर कॉमेडी मूवी में सुनील अपने अजीज दोस्त और हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की कलाकार अक्षय कुमार और परेश रावल संग पर्दे पर कॉमेडी से धमाल मचाते हुए दिखाई देंगे।

आमिर खान के परिवार की बोल्ड हसीना,हॉटनेस में सबसे आगे

सुपरस्टार आमिर खान की भतीजी अपनी हॉटनेस के दम पर बी टाउन में धमाल मचाती रहती है।

हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार्स के परिवार को लेकर सिनेमाई गलियारों में काफी बातचीत की जाती है। इस आधार पर आज हम आपको अभिनेता आमिर खान की फैमिली को उस बोल्ड हसीना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इंटरनेट पर अपनी हॉटनेस का जलवा बिखेरती रहती है। इतना ही नहीं अपनी शानदार फिल्मों के जरिए आमिर की भतीजी परिवार का नाम भी रोशन कर रही है। हाल ही में इस अदाकारा को मृणाल ठाकुर और अदिवी शेष की फिल्म डकैत भी देखा गया है।

आमिर खान की भतीजी कौन?

सुपरस्टार आमिर खान के पिता का नाम ताहिर हुसैन था और उनके छोटे भाई का नाम नासिर हुसैन। ये दोनों अपने समय के हिंदी सिनेमा के दो बड़े दिग्गज फिल्ममेकर रहे।

नासिर के बेटे का नाम मंसूर खान है,जोकि रिश्ते में आमिर के कजिन लगते हैं। मंसूर की बेटी का नाम जैन मैरी खान हैं,जिनके चाचा आमिर खान हैं। जैन लंबे समय से इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस के तौर पर एक्टिव हैं और बी टाउन में खान परिवार का नाम आगे बढ़ा रही हैं। इतना ही नहीं जैन मैरी खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।

जैन के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद इन तस्वीरों को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह रियल लाइफ में हॉटनेस में काफी आगे हैं और आए दिन वह इंटरनेट पर अपनी बोल्डनेस से कहर बरपाती रहती हैं। फैंस को भी जैन मैरी खान का हॉट और बोल्ड लुक वाला अंदाज काफी पसंद आता है। गौर किया जाए जैन मैरी खान की निजी जिंदगी की तरफ तो उन्होंने साल 2021 में आकाश मोहमिन संग शादी रचाई। 31 वर्षीय जैन हद से ज्यादा खूबसूरत हैं और इस मामले में वह इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियों पर भारी पड़ती हुई नजर आती हैं।

जैन मैरी खान का एक्टिंग करियर

बतौर एक्ट्रेस साल 2020 में जैन मैरी खान ने फिल्म मिसेज सीरियल किलर से अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया था। इसके बाद बड़े पर्दे से लेकर ओटीटी तक जैन ने अपनी शानदार अदाकारी की छाप छोड़ी। इस दौरान वह मेड इन हेवन और इलीगल जैसी वेब सीरीज में भी नजर आई हैं। उनकी मूवीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें-मोनिका ओ माय डार्लिंग और डकैत के नाम शामिल हैं। हालिया रिलीज साउथ फिल्म डकैट में जैन एक लेडी पुलिस ऑफिसर की भूमिका में दिखाई दी हैं।

नए किरदार में नजर आएंगे मनोज बाजपेयी

आज 23 अप्रैल को मनोज बाजपेयी के जन्मदिन पर द केरल स्टोरी के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने गवर्नर- द साइलेंट सेवियर नाम की एक नई फिल्म की घोषणा की है। इस फिल्म में अदा शर्मा मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आएंगी। फिल्म की कहानी के बारे में दो पोस्टर और शीर्षक के अलावा ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। गवर्नर 12 जून, 2026 को रिलीज होगी।

सामने आया फिल्म का पोस्टर

गवर्नर के दो पोस्टरों से एक ऐसे पद के दबाव की झलक मिलती है, जिसका बोझ बहुत भारी होता है। हालांकि, पोस्टरों में अभिनेताओं के चेहरे नहीं दिखाए गए हैं। पहले पोस्टर में सरकारी डेस्क के पीछे खाली कुर्सी दिखाई गई है, जो यह संकेत देती है कि यह कोई साधारण पद नहीं है - यह एक ऐसी कुर्सी है जिसके साथ जिम्मेदारी, निर्णय और ऐसे परिणाम जुड़े होते हैं जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं। कुर्सी को सिर्फ एक कुर्सी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बताने वाली पंक्ति इसे और भी भारी बना देती है, मानो जो भी इस पर बैठेगा, वह इसके बोझ से बच नहीं पाएगा। दूसरी तस्वीर इसे और भी व्यक्तिगत बना देती है। कुर्सी की जगह, हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो संभवतः उस पर बैठेगा - एक धुंधले गलियारे में अकेला चलता हुआ, हाथ में ब्रीफकेस लिए, किसी अपरिहार्य चीज़ की ओर। अगर मैं असफल हुआ... तो भारत असफल हुआ यह पंक्ति कहानी को महज एक राजनीतिक नाटक से एक गहन मानवीय अनुभव में बदल देती है। कैप्शन में लिखा था, आज हम एक विश्व शक्ति हैं क्योंकि एक गुमनाम नायक ने एक अनकही जंग लड़ी। गवर्नर 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है।

खेल समाचार

लामीने यामाल को पैर की चोट, बार्सिलोना के बाकी मैचों से बाहर

बार्सिलोना,23 अप्रैल 2026। स्पेन के युवा फुटबॉलर लामीने यामाल को बाएं पैर की मांसपेशी में चोट लगने के कारण मौजूदा ला लीगा सीज़न के बाकी मैचों से बाहर कर दिया गया है। बार्सिलोना क्लब ने गुरुवार को इसकी आधिकारिक जानकारी दी। क्लब के अनुसार खिलाड़ी अपने बाएं पैर की मसल इंजरी से उबरने के लिए कंजरवेटिव ट्रीटमेंट प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। बार्सिलोना ने स्पष्ट किया है कि 18 वर्षीय यामाल अब लीग के बचे हुए छह मुकाबलों में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। यह फैसला मेडिकल जांच और उपचार योजना के आधार पर लिया गया है,ताकि खिलाड़ी पूरी तरह से फिट होकर लंबे समय के लिए मैदान पर वापसी कर सकें।

यह चोट उन्हें बुधवार को सेल्टा विगो के खिलाफ खेले गए मुकाबले में लगी थी। इस मैच में बार्सिलोना ने 1-0 से जीत दर्ज की थी। इसी मैच के दौरान पेनल्टी को गोल में बदलते समय यामाल को यह चोट लगी, जिसके बाद उन्हें असहज महसूस हुआ और मेडिकल टीम ने तुरंत उनकी जांच की। क्लब की मेडिकल टीम ने प्रारंभिक जांच के बाद यह निर्णय लिया कि किसी भी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता नहीं है और खिलाड़ी को फिलहाल आराम और गैर-आक्रामक इलाज की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसी कारण कंजरवेटिव ट्रीटमेंट अपनाया गया है,जिसमें दवाइयों,फिजियोथेरेपी और धीरे-धीरे रिकवरी शामिल होती है। बार्सिलोना ने यह भी बताया है कि हालांकि यामाल इस सीज़न के घरेलू लीग मैचों से बाहर रहेंगे, लेकिन उनके फीफा वर्ल्ड कप से पहले पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद है। क्लब का मेडिकल स्टाफ लगातार उनकी स्थिति पर नजर रखेगा और रिकवरी के अनुसार ट्रेनिंग में वापसी का निर्णय लिया जाएगा। यामाल इस सीज़न में बार्सिलोना के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। अपनी गति, तकनीक और आक्रामक खेल शैली के कारण उन्होंने टीम के लिए कई मौकों पर अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में उनके बाहर होने को टीम के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति माना जा रहा है, खासकर सीज़न के अंतिम चरण में जब अंक तालिका में स्थिति निर्णायक होती है।

लेक और फेयरप्लेक्स ने पोमोना में नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड का किया शिलान्यास

लॉस एंजिल्स,23 अप्रैल 2026। नाइट राइडर्स और फेयरप्लेक्स ने कैलिफ़ोर्निया के एलए काउंटी के पोमोना में नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में भूमि पूजन का जश्न मनाया। यह अमेरिका में क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल था और 2028 के ओलंपिक खेलों से पहले लॉस एंजिल्स को इस खेल के तेज़ी से विकास में एक अहम केंद्र के तौर पर स्थापित करता है। नागरिक नेता, दुनिया भर के खेल हितधारक और सामुदायिक साझेदार अमेरिका में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुए।

इस समारोह में नागरिक नेता, दुनिया भर के खेल हितधारक और सामुदायिक साझेदार एक साथ आए और इस बात पर ज़ोर दिया कि यह दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया के पहले समर्पित क्रिकेट स्थलों में से एक है और इस परियोजना का महत्व है। यह विकास मार्च में एलएकेआर के स्टेडियम की घोषणा के बाद हुआ है और यह आगामी मेजर लीग क्रिकेट सीज़न के लिए टीम का घरेलू मैदान होगा। इस कार्यक्रम में नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स के सह-मालिक श्री शाहरुख खान का एक विशेष वीडियो संदेश, नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स के सीईओ वेंकी मैसूर और फेयरप्लेक्स के अध्यक्ष और सीईओ वाल्टर मार्केज़ के उद्घाटन भाषण शामिल थे; अन्य विशिष्ट वक्ताओं में पोमोना के मेयर टिम सैंडोवल शामिल थे;आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता; लॉस एंजिल्स के पूर्व मेयर और भारत में पूर्व अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी;एलए 28 के चीफ ब्रांड और कम्युनिकेशंस ऑफिसर निकोलो कैंप्रियानी।

पीएसएल में हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा!

पाकिस्तान सुपर लीग में तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ के बीच भारी ड्रामा हो गया... जिसके बाद अंपायर्स को बीच बचाव करना पड़ा...

नई दिल्ली ,23 अप्रैल 2026। पाकिस्तान सुपर लीग में रावलपिंडीज और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच खेले गए मुकाबले में रोमांच के साथ-साथ तीखा तनाव भी देखने को मिला। मैच के दौरान रावलपिंडीज के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर और इस्लामाबाद के ऑलराउंडर फहीम अशरफ के बीच मैदान पर जबरदस्त बहस हुई। यह वाकया तब शुरू हुआ जब आमिर ने एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अशरफ को आउट किया। विकेट लेने के बाद आमिर ने अपने चिर-परिचित आक्रामक अंदाज में अशरफ को विदाई दी, जिसके बाद बल्लेबाज गुस्से से लाल पीला हो गया।

फहीम अशरफ ने दिखाया बल्ला

फहीम अशरफ ने वापस जाते समय पलटकर आमिर की तरफ बल्ला दिखाकर कड़ी प्रतिक्रिया दी जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। मैदान पर माहौल काफी गरमा गया था जिसे देख साथी खिलाड़ियों और अंपायरों को तुरंत बीच-बचाव करना पड़ा। इस घटना ने मैच में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया हालांकि समय रहते स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया।

रावलपिंडीज ने जीता पहला मैच

मैदान पर मचे इस घमासान के बीच रावलपिंडीज के लिए यह दिन थोड़ा सा अच्छा रहा। टीम ने आखिरकार अपने हार के सूखे को खत्म करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड पर 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। लगातार 8 मैच हारने के बाद यह रावलपिंडीज की इस सीजन की पहली जीत है। हालांकि टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है।

137 रन बना पाई इस्लामाबाद की टीम

इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की शुरुआत खराब रही और टीम पूरे ओवरों में महज 137 रन ही बना सकी। ओपनिंग बल्लेबाज डेवोन कॉनवे (40 रन) और निचले क्रम में क्रिस ग्रीन (29 रन) की पारियों के बावजूद टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही। रावलपिंडीज के लिए मोहम्मद आमिर और साद मसूद ने दो-दो विकेट झटककर इस्लामाबाद की कमर तोड़ दी।

रिजवान ने खेली 145 रन की पारी

138 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रावलपिंडीज ने शुरुआती झटका लगने के बाद संभलकर बल्लेबाजी की। मोहम्मद रिजवान (45 रन) और कामरान गुलाम (42 रन) के बीच हुई 78 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी ने जीत की नींव रखी। इन दोनों के आउट होने के बाद डेरिल मिचेल ने मोर्चा संभाला और नाबाद 32 रन बनाकर 18.1 ओवर में टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया। इस्लामाबाद की ओर से शादाब खान, इमाद वसीम और क्रिस ग्रीन ने विकेट तो लिए लेकिन वे रनों की गति पर अंकुश नहीं लगा सके।

मिचेल स्टार्क दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ेंगे

1 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेल सकते हैं

मेलबर्न,23 अप्रैल 2026। ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज़ गेंदबाज़ मिचेल स्टार्क को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2026 इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है और वह जल्द ही दिल्ली कैपिटल्स टीम में शामिल होंगे। स्टार्क, जो कोहनी और कंधे की चोट के कारण जनवरी से बाहर हैं, 1 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ़ मैच में वापसी कर सकते हैं। स्टार्क ने पहले भी इंटरनेशनल लेवल पर अपना दबदबा बनाया था, इंग्लैंड के खिलाफ़ एशेज सीरीज़ में सबसे ज़्यादा विकेट लेकर प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ का अवॉर्ड जीता था। दिल्ली कैपिटल्स में उनके शामिल होने को टीम के लिए एक बड़ा बूस्ट माना जा रहा है, जो अभी तीन जीत और तीन हार के साथ आईपीएल पॉइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर है। 2026 आईपीएल सीज़न में शुरुआती मैचों में कई विदेशी खिलाड़ियों के न होने की वजह से विवाद हुआ है, जिससे खिलाड़ियों की उपलब्धता और टीम की ताकत पर बहस छिड़ गई है। स्टार्क ने इंस्टाग्राम पर अपनी रिकवरी के अपडेट शेयर किए थे, जिसमें उन्होंने कन्फर्म किया था कि वह चोट के कारण बाहर थे। अब पूरी तरह से फिट होने के बाद, उनसे दिल्ली कैपिटल्स के बॉलिंग अटैक को मज़बूत करने के लिए अपनी पेस और अनुभव लाने की उम्मीद है।

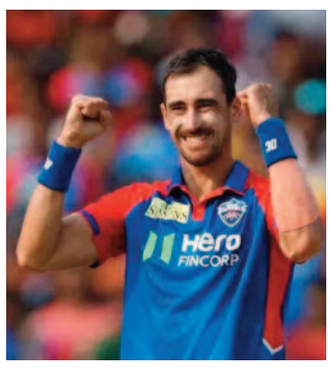

पिछले साल, स्टार्क ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए 11 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 14 विकेट लिए और टीम के लिए ज़रूरी ब्रेकथ्रू दिए। जल्दी स्ट्राइक करने और विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखने की उनकी काबिलियत उन्हें फ्रेंचाइजी के लिए एक अहम एसेट बनाती है। दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ ने स्टार्क की वापसी को लेकर उम्मीद जताई है, और कहा है कि उनकी मौजूदगी से बाकी मैचों में टीम की संभावनाएँ मज़बूत होंगी।

मैनचेस्टर सिटी ने टॉप पर पहुंचकर टर्फ मूर में मामूली जीत के साथ बर्नले को रेलीगेट कर दिया

वेलिंगटन,23 अप्रैल 2026। मैनचेस्टर सिटी ने टर्फ मूर में 1-0 की मुश्किल जीत के साथ आर्सेनल का प्रीमियर लीग टॉप पर छह महीने का स्टे खत्म किया और बर्नले को रेलीगेशन की सज़ा दी। पांच मिनट बाद एर्लिंग हालैंड के क्लिनिकल फिनिश से सिटी के गोल डिफेंस को बढ़ाने का रास्ता बन सकता था,लेकिन बर्नले के गहरे दबाव के कारण उनमें धार की कमी थी। हालैंड ने पोस्ट पर हिट किया और दूसरे मौके भी मिले, क्योंकि सिटी ने खुद को सेफ्टी मार्जिन देने की कोशिश की,लेकिन पेप गार्डियोला की टीम को हैरानी की बात है कि बहुत कम अंतर से जीत हासिल करनी पड़ी। आर्सेनल को हराने के बाद, वे अब गोल करने की टेबल में सबसे आगे हैं, दोनों टीमों के 33 गेम में 70 पॉइंट हैं और गोल का अंतर भी लगभग 37 है। स्कॉट पार्कर की बर्नले के लिए यह अब सच हो गया है क्योंकि वे 20 पॉइंट पर अटके हुए हैं, और सिर्फ़ चार गेम बाकी रहते हुए वे सेफ़्टी ज़ोन से 13 पॉइंट पीछे हैं।

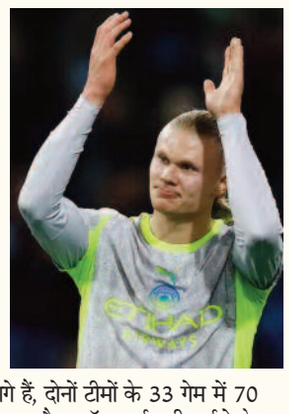

शासकीय कर्मचारियों पर राजनीतिक गतिविधियों की पाबंदी का आदेश 24 घंटे में ही स्थगित

रायपुर,23 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवकों के राजनीतिक दलों या संगठनों में सक्रिय सदस्यता और अन्य पदों पर आसीन होने को लेकर जारी अपने ही आदेश को महज़ एक दिन के भीतर स्थगित कर दिया है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को पत्र जारी किया था। इसमें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं होगा और न ही किसी राजनीतिक गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेगा। इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया था कि शासकीय कर्मचारी बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी शासकीय या अशासकीय संस्था, समिति, संगठन या निकाय में कोई पद धारण नहीं करेगा। साथ ही ऐसे किसी दायित्व को स्वीकार करने से भी रोका गया था जिससे उसकी प्रशासनिक निष्पक्षता प्रभावित हो सकती हो। नियमों के उल्लंघन पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी।हालांकि, इस आदेश के जारी होने के अगले ही दिन सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नया पत्र जारी कर पूर्व निर्देशों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। इस त्वरित यू-टर्न ने प्रशासनिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं, और अब यह चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को महज़ 24 घंटे में ही अपना निर्णय वापस लेना पड़ा।

सरायपाली में कार में लगी आग कूदने से चालक का जान बचा

महासमुंद,23 अप्रैल 2026। जिले के सरायपाली क्षेत्र में गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब पदमपुर रोड स्थित गुरु नानक चौक के पास अचानक एक चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार, कार में आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। प्रारंभिक अंदेशा शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का जताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं नगर पालिका की दमकल वाहन ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। इस घटना से आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में दहशत फैल गई और कुछ समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि कार सवार खेम लाल साहू (पिता अंगार साहू) ग्राम दुलारपाली, सरायपाली का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

जीएसटी बकाया वसूली मामला : हाईकोर्ट से याचिकाकर्ता को राहत,प्री-डिपॉजिट और अंडरटेकिंग पर वसूली कार्रवाई पर रोक

बिलासपुर,23 अप्रैल 2026। जीएसटी बकाया वसूली से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मामला मां काली इंडस्ट्रीज की ओर से दायर रिट याचिका से संबंधित है, जिसमें राज्य कर विभाग द्वारा पारित आदेशों और वसूली कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने 4 नवंबर 2022 और 28 मार्च 2024 के आदेशों के साथ-साथ 16 जनवरी 2026 की अटैचमेंट नोटिस को चुनौती दी थी। इन आदेशों के तहत जीएसटी बकाया की वसूली की कार्रवाई की जा रही थी। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को जारी सर्कुलर का हवाला दिया। इस सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि जब तक जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन नहीं होता,तब तक अपील करने वाले करदाताओं को राहत दी जा सकती है, बशर्ते वे निर्धारित प्री-डिपॉजिट जमा करें और एक अंडरटेकिंग दें। साथ ही 17 सितंबर 2025 की अधिसूचना का भी उल्लेख किया गया, जिसमें अपील दायर करने की समय-सीमा 30 जून 2026 तक बढ़ाई गई है। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकलपीठ ने कहा कि इस मामले में अब आगे किसी न्यायिक निर्णय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा पहले ही स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी कि वह संबंधित अधिकारी के समक्ष अंडरटेकिंग/घोषणा प्रस्तुत करे कि ट्रिब्यूनल बनने पर अपील करेगा। जीएसटी कानून के तहत निर्धारित प्री-डिपॉजिट राशि 15 दिनों के भीतर जमा करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता तय समय में प्री-डिपॉजिट जमा कर देता है और अंडरटेकिंग देता है, तो शेष बकाया राशि की वसूली पर रोक लग जाएगी।

फास्टरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा..बेटी की शादी की खरीदारी कर लौट रहे दंपत्ति की मौत

मुंगेली,23 अप्रैल 2026। मुंगेली जिले के फास्टरपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की घटना सामने आई है, जिसमें बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे एक दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब पति-पत्नी शादी के लिए खरीदारी कर अपने गांव लौट रहे थे। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है और परिवार पर दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जानकारी के अनुसार, ग्राम लगरा निवासी इंद्रेश्वर तिवारी (56 वर्ष) और उनकी पत्नी देवेश्वरी तिवारी (48 वर्ष) अपनी बेटी की शादी की तैयारियों को लेकर मुंगेली शहर पहुंचे थे। दोनों ने वहां से कपड़े और शादी से जुड़ा अन्य जरूरी सामान खरीदा और देर शाम बाइक से अपने घर लौट रहे थे। परिवार में शादी की खुशियों का माहौल था और सभी तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। लेकिन यह खुशियां अचानक दर्दनाक हादसे में बदल गईं। नवोदय विद्यालय दाबो के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पति-पत्नी सड़क पर दूर जा गिरे और उन्हें गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही फास्टरपुर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जग्गी हत्याकांड : अमित जोगी को मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर पर लगाई रोक

सीबीआई से मांगा जवाब,उम्रकैद-अपील दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई

रायपुर,23 अप्रैल 2026। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड मामले में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी(जेसीसी-जे) सुप्रीमो अमित जोगी को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 25 मार्च 2026 (जिसमें अपील दायर करने की अनुमति दी गई) और दो अप्रैल 2026 (जिसमें अपील को स्वीकार किया गया) को संयुक्त रुप से स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जोगी के सरेंडर करने के आदेश पर फिलहाल रोक(स्टे) लगा दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। सीबीआई का जवाब आने तक अमित जोगी के सरेंडर पर रोक लगी रहेगी। अमित जोगी की दोनों अपील पर सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई। अमित जोगी की ओर से दो हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अमित जोगी को तीन हफ्ते में सरेंडर करने के निर्देश दिये थे। हाईकोर्ट ने उन्हें हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों मामले की एक साथ सुनवाई चल रही है। इस मामले में जेसीसी-जे का कहना है कि अमित जोगी के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया निर्णय ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जोगी को दिए गए आजीवन कारावास के आदेश पर रोक (स्टे) लगा दी है। यह निर्णय न केवल न्यायपालिका में विश्वास को और मजबूत करता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि सत्य को अस्थायी रूप से परेशान किया जा सकता है, परंतु उसे पराजित नहीं किया जा सकता। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ इस न्यायपूर्ण निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट का हृदय से आभार व्यक्त करती है। पार्टी का मानना है कि यह सत्य और न्याय की ऐतिहासिक विजय है, जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों और न्याय की गरिमा को पुनः स्थापित किया है। मुख्य प्रवक्ता अधिवक्ता भगवानू नायक ने कहा कि हमारी पार्टी न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास रखती है और आज का यह फैसला उसी विश्वास को और सुदृढ़ करता है।

2003 में गोली मारकर की गई थी हत्या

4 जून 2003 को एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे। जिनमें से बुल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे। अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को सजा मिली थी। हालांकि,31 मई 2007 को रायपुर की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया था। रामअवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जिस पर अमित के पक्ष में स्टे लगा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केस को हाईकोर्ट भेज दिया। हाईकोर्ट ने ट्रॉयल कोर्ट के फैसले को गलत बताया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा था कि यह मानना हास्यास्पद है कि बाकी दोषियों ने अमित जोगी को खुश करने के लिए उनकी जानकारी के बिना इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया।

अमित जोगी बोले...न्यायपालिका पर मुझे पूरा विश्वास

अमित जोगी ने पिछली बार फेसबुक पर लिखा था कि, सर्वोच्च न्यायालय ने आज दोनों मामलों को एक साथ टैग कर दिया है। मेरी कानूनी टीम का हृदय से आभार। न्यायपालिका पर मुझे पूर्ण विश्वास है।

सतीश जग्गी का आरोप...तत्कालीन राज्य सरकार की प्रायोजित थी हत्या

हाईकोर्ट में अपील पर रामावतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी के अमित जोगी की दोषमुक्ति के खिलाफ पेश क्रिमिनल अपील पर उनके अधिवक्ता बीपी शर्मा ने तर्क दिया था। उन्होंने बताया था कि हत्याकांड की साजिश तत्कालीन राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित थी। जब सीबीआई की जांच शुरू हुई,तब सरकार के प्रभाव में सारे सबूतों को मिटा दिया गया था। ऐसे केस में सबूत अहम नहीं हैं,बल्कि षड्यंत्र का पर्दाफाश जरूरी है। लिहाजा,इस केस के आरोपियों को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने खारिज की आईएएस रानू साहू के रिश्तेदारों की सभी याचिकाएं

मनी लांड्रिंग केस में ईडी ने अटैच की है करोड़ों की संपत्ति

बिलासपुर,23 अप्रैल 2026। हाईकोर्ट ने कोरबा के पूर्व व निलंबित कलेक्टर आईएएस रानू साहू के रिश्तेदारों की करोड़ों की संपत्ति अटैच किए जाने के खिलाफ पेश सभी याचिका को खारिज कर दिया है। मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डीबी में सुनवाई हुई। बता दें कि कोल लेवी वसूली व मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी ने रानू साहू के रिश्तेदार तुषार साहू, रानू साहू, कजिन पंकज कुमार साहू, पीयूष कुमार साहू, रानू साहू के भाई पूनम साहू, रानू साहू की बहन, अरुण कुमार साहू रानू साहू के पिता और लक्ष्मी साहू रानू साहू की मां, सहलिनी साहू पीयूष कुमार साहू की पत्नी और रेवती साहू रानू साहू की आंटी की सम्पत्ति अटैच किया है। इस कार्रवाई के खिलाफ सभी ने अलग-अलग याचिका पेश की थी। याचिका में कहा गया है कि ईडी ने रानू साहू के कोरबा कलेक्टर रहने से पूर्व में खरीदी गई संपत्ति को अटैच किया है। अपीलेट ट्रिब्यूनल से अपील खारिज किया गया है, जो गलत है। इसके अलावा एफआईआर में उनका नाम नहीं है। अटैच प्रॉपर्टी को मुक्त कराने की मांग की गई। मामले में चीफ जस्टिस की डीबी ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा, जुर्म से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी PMLA के तहत अपने आप अटैचमेंट से सुरक्षित नहीं होती है। सेक्शन 2(1)(u) के तहत 'जुर्म से हुई कमाई' की परिभाषा में न सिर्फ़ खराब प्रॉपर्टी शामिल है, बल्कि उसकी बराबर कीमत भी शामिल है, जो एक बड़े कानूनी इरादे को दिखाता है। जहां असली कमाई मौजूद नहीं है या उसका पता नहीं चल पा रहा है, वहां अधिकारी उतनी ही कीमत की दूसरी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, भले ही वे पहले कानूनी तौर पर खरीदी या हासिल की गई हों। ऐसी अटैचमेंट का मकसद अपराधियों को जुर्म से होने वाले आर्थिक फ़ायदों को अपने पास रखने से रोकना है। एनफोर्समेंट अथॉरिटी के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह सीधे सबूतों से यह साबित करे कि जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, वह क्राइम से हुई कमाई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में काम करने का तरीका अक्सर घुमावदार और साफ न दिखने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़ा होता है, जिससे सीधे सबूत मिलना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ कोर्ट ने सभी याचिका को खारिज कर दिया है।

तखतपुर में कुत्तों का आतंक...पागल कुत्तों ने 25 को काटा,15 लोग पहुंचे अस्पताल

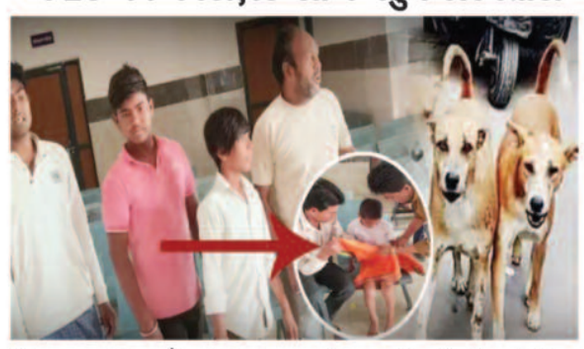

बिलासपुर,23 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले के तखतपुर में गुरुवार को पागल कुत्तों ने कुछ ही घंटों के भीतर एक के बाद 25 लोगों को बुरी तरह काट लिया। कुत्तों के हमलों के बाद अब तक बच्चों समेत सभी 15 घायल तखतपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उनका इलाज किया गया।

तखतपुर के अलग-अलग क्षेत्रों में गुरुवार को 7 से 8 पागल कुत्तों ने सड़क पर चल रहे करीब 25 लोगों को काट लिया। यह घटना चंडी चौक,कुरानकापा, पुराना थाना क्षेत्र,भथरी और मुक्तिधाम रोड में हुई। कुत्ते बिना किसी कारण राह चल रहे लोगों पर हमला कर रहे थे। कई लोग घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के अनुसार,अब तक बच्चे और बुजुर्ग समेत 15 लोग कुत्तों के काटने की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में सभी का इलाज किया जा रहा है और एंटी रेबीज इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अभी तक पागल कुत्तों को काबू में नहीं किया जा सका है। अगर इन कुत्तों को जल्द नहीं पकड़ा गया तो और लोग घायल हो सकते हैं।

आरटीई एडमिशन पर रोक....प्राइवेट-स्कूलों ने शिक्षा मंत्री को भेजा पत्र

रायपुर,23 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेशभर के निजी स्कूल 1 मार्च से असहयोग आंदोलन पर हैं। 4 अप्रैल को संगठन ने निर्णय लिया कि आरटीई के तहत लॉटरी से आबंटित वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 17 अप्रैल को शिक्षकों और संचालकों ने काली पट्टी लगाकर विरोध किया, जबकि 18 अप्रैल को स्कूल बंद रखे गए। इस आंदोलन के तहत आज विभिन्न जिलों के निजी स्कूलों ने डाक के माध्यम से स्कूल शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। संगठन का आरोप है कि विभाग उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहा है और मांग की अनदेखी की जा रही है। संगठन ने बताया कि 24 अप्रैल को प्रदेशभर में जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपनी समस्याएं रखी जाएंगी और स्कूल शिक्षा विभाग की लापरवाही से अवगत कराया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर रणनीति तैयार कर ली गई है। 23 अप्रैल को हुई सचिव स्तरीय वार्ता बेनतीजा रही। संगठन ने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर इसे और तेज किया जाएगा। एसोसिएशन ने शासकीय स्कूलों में प्रति विद्यार्थी खर्च सार्वजनिक करने की मांग की है, ताकि निजी स्कूलों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि तय हो सके।

13 साल तक मचाया तांडव...अब एसपी ऑफिस पहुंचकर महिला नक्सली ने डाले हथियार

राजनांदगांव,23 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव रेंज में लाल आतंक की कमर तोड़ने में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। बस्तर के रावघाट एरिया कमेटी में एरिया कमेटी मेंबर के पद पर सक्रिय खूंखार महिला नक्सली उर्मिला उर्फ टेटकी (28) ने मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के जिला मुख्यालय में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वह बुधवार शाम चुपचाप पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। अधिकारियों के मुताबिक, गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में उसका विधिवत सरेंडर कराया जाएगा। उर्मिला का सरेंडर मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है,क्योंकि वह इस इलाके की 'आखिरी माओवादी कैडर' बताई जा रही है। उर्मिला मूलतः मानपुर ब्लॉक के मुंजाल गांव की रहने वाली है। उसके नक्सली सफर की दास्तां चौंकाने वाली है। उसने महज 15 साल की उम्र में सशस्त्र माओवादियों के साथ बस्तर के बीहड़ों में कदम रखा था। देखते ही देखते वह संगठन में रावघाट एरिया कमेटी मेंबर जैसे बड़े पद तक पहुंच गई। पिछले 13 साल तक वह बस्तर के विभिन्न इलाकों में पुलिस के खिलाफ कई बड़ी नक्सली वारदातों और एंबुश में सक्रिय भूमिका निभाती रही। रावघाट जैसे अति-संवेदनशील इलाके में उसकी मौजूदगी पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। सरेंडर के बाद उर्मिला ने बताया कि वह संगठन में बाहरी कैडरों के भेदभाव,शोषण और पुलिस के बढ़ते दबाव से तंग आ चुकी थी। वह अब मुख्यधारा में लौटकर अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जीना चाहती है। उसके सरेंडर से रावघाट एरिया कमेटी के नक्सली नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगा है, जिससे बस्तर में नक्सलियों के पैर उखड़ने तय हैं। पुलिस उर्मिला से संगठन की रणनीतियों, अन्य बड़े लीडरों की लोकेशन और हथियार डिपो के बारे में अहम जानकारी हासिल कर रही है,जो आने वाले ऑपरेशंस के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

शिक्षकों की बल्ले-बल्ले! हाई कोर्ट का आदेश-'पुरानी सेवा' को पेंशन के लिए मानना ही होगा!

रायपुर,23 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए न्याय के गलियारे से एक अत्यंत सुखद और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों की 'संविलियन' से पूर्व की सेवा अवधि को पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी की पिछली सेवाओं को मान्यता दी गई है, तो उसे पेंशन के निर्धारण में भी अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए। यह निर्णय राज्य के हजारों शिक्षकों के भविष्य के लिए सुरक्षा कवच साबित होगा।

शिक्षक राजेंद्र प्रसाद पटेल की कानूनी लड़ाई और न्याय की जीत : यह पूरा मामला चिरमिरी नगर निगम में पदस्थ शिक्षक राजेंद्र प्रसाद पटेल द्वारा दायर की गई एक याचिका से शुरू हुआ था। राजेंद्र प्रसाद पटेल ने हाई कोर्ट में अपनी व्यथा रखते हुए कहा था कि संविलियन (मर्जर) होने के बाद भी प्रशासन उनकी पूर्व में की गई सेवाओं को पेंशन गणना में शामिल नहीं कर रहा है। उन्होंने इसे अपने मौलिक अधिकारों का हनन और सेवा के साथ अन्याय बताया। एकल पीठ ने पहले ही उनके पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसे चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अगुवाई वाली बेंच ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ देने के लिए शिक्षककर्मियों द्वारा की गई पिछली सेवा का योगदान अमूल्य है। इसे केवल नियमों की दुहाई देकर खत्म नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आदेश दिया कि शिक्षकों के पेंशन प्रकरणों का निर्धारण उनकी पूर्व सेवा गणना के आधार पर ही किया जाए, ताकि उन्हें उनके हक का पूरा आर्थिक लाभ मिल सके।

राज्य सरकार के तर्क और कोर्ट द्वारा उनकी अस्वीकृति

डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपने पक्ष में दलील दी कि संविलियन के समय जो नियम और शर्तें तय की गई थीं, पेंशन का निर्धारण उन्हीं के आधार पर होना चाहिए। सरकार का तर्क था कि संविलियन के बाद शिक्षक एक नए कैडर का हिस्सा बने हैं, इसलिए पुरानी सेवा को इसमें शामिल करना तकनीकी रूप से जटिल है। हालांकि,कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब आप एक तरफ पूर्व सेवा की गणना को मान्यता दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पेंशन के समय उसे नजरअंदाज करना न्यायसंगत नहीं है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)